



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1997/वैशाख 27, 1919

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1997/VAISAKHA 27, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation

भाग II—खण्ड—3 उप-खंड (ii)
PART II—Section—3 Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांख्यिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
(न्यायिक अनुभाग)
सूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1251.—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसार
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कृष्ण कुमार जोहरी,
प्लोडर, ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक
आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का
आपेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे
पास भेजा जाए।

[सं.एफ 5(109)/97-न्यायिक]

एन. सी. जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं
अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Legal Affairs)
(Judicial Section)

NOTICE

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1251.—Notice is hereby given by the Competent
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956
that application has been made to the said Authority, under

Rule 4 of the said Rules, by Shri Krishna Kumar Johri, Pleader
for appointment as a Notary to practise in Pilibhit (U.P.)

2. Any objection to the appointment of the said per-
son as a Notary may be submitted in writing to the under-
signed within fourteen days of the publication of this notice.

[No. F. 5(109)/97-Judl.]

N. C. JAIN, Competent Authority &
Addl. Legal Advisor

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1997

का. आ. 1252.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता,
1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सी. सहाय, अपर विधि सलाहकार,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा विचारण
न्यायालयों में संस्थित मामलों तथा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिन
पर पूर्वोक्त धारा के उपबंध लागू होते हैं, में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण
अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलें/पुनरीक्षणों
अथवा अन्य विषयों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप
में नियुक्त करती है।

[सं.—225/1/97-ए. वी. डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSION**

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 25th April, 1997

S.O. 1252.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri C. Sahay, Additional Legal Adviser, Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in the trial courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by Law in any State or Union Territory which the provision of the aforesaid section apply.

[No. 225/1/97-AVD. II]

HARI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1997

का. आ. 1253.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित अभियोजन अधिकारी का ऐसे किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में जिस पर पूर्वोक्त धाराओं के उपबंध लागू होते हैं, विचारण न्यायालयों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मामलों तथा विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में इन मामलों से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा अन्य विषयों के संचालन कि लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :

- (1) श्री हरबंस लाल चौपड़ा
- (2) श्री शंकर प्रसाद टन्टी

[संख्या 225/1/97-ए. वी. डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1997

S.O. 1253.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act, No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints the following prosecuting officers of the Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutor for the conduct of cases instituted by Delhi Special Police Establishment in the trial courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate courts established by Law in any State or Union Territory to which the provision of the aforesaid section apply.

- (1) Shri Harbans Lal Chopra
- (2) Sh. Shankar Prasad Tanti

[No. 225/1/97-AVD.II]

HARI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1997

का. आ. 1254.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 25 की उपधारा (1 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. नटराजन को भारत के किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र जिन पर पूर्वोक्त धारा के उपबंध लागू होते हैं, में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा संस्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में किसी मामले अथवा मामलों के वर्ग का संचालन करने के प्रयोजन के लिए सहायक लोक अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो नियुक्त करती है।

[सं. 225/6/97-ए. वी. डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 1997

S.O. 1254.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-A) of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sh. S. Natarajan, as Assistant Public Prosecutor, Central Bureau of Investigation for the purpose of conducting any case or class of cases in the courts of Magistrates instituted by Delhi Special Police Establishment before the courts of Magistrates in any State or Union Territory of India to which the provision of the aforesaid section apply.

[No. 225/6/97-AVD.-II]

HARI SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1997

का. आ. 1255.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप धारा (8) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा विशेष न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में ए. के. जैन एवं अन्य के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नियमित मामला संख्या 1 ए/92 ए. सी. यू.-4 में अभियोजन का संचालन एवम् सम्बंधित कार्यवाही करने हेतु श्री के. एन. शर्मा, अधिवक्ता, दिल्ली को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/4/97-ए. वी. डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1997

S.O. 1255.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government vide order dated 20-3-97 hereby appoints Shri K. N. Sharma, Advocate, Delhi as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution and related proceedings of the Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 1(A)/92-ACU (IV) State Vs. A. K. Jain and others, in the court of Special Judge, Tis Hazari, Delhi.

[No. 225/4/97-AVD-II]

HARI SINGH, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1256.—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम सरकार द्वारा पोलिटिकल (ए) विभाग की अधिसूचना सं. पी. एल. ए.-171/96-32ए तारीख 23-10-1996 दी गई सहमति से भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराधों जो श्री पराग कुमार दास, पत्रकार और महासचिव, मानव अधिकार संग्राम समिति की तारीख 17-5-1996 को 3-00 बजे अपराह्न में जब वे असम जातीय विद्यालय, राजगढ़ मार्ग गुवाहाटी के मुख्य द्वार के सामने कक्षा III के विद्यार्थी अपने अवयस्क पुत्र श्री रोहित दास के साथ विद्यालय से बाहर आ रहे थे, दिन दहाड़े की गई उनकी हत्या से संबंधित यह मामला चांदमारी थाना, गुवाहाटी असम में प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं. 207/96 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, ऊपर वर्णित अपराधों के संबंध में या उनसे संसक्त प्रत्यक्ष, दुष्प्रेरण और पड़ोस तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत होने वाले वैसे ही संयोजन के अनुक्रम में किया गया या किए गए कोई अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य में करती है।

[संख्या 228/19/97-ए.वी.डी.-II]

हरि सिंह, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1256.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Assam Political (A) Department Notification No. PI.A-171/96/32-A dated 23-10-1996, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Assam for the investigation of the offences punishable under section 302 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) of Case FIR NO. 207/96 registered at Chandmari Police Station, Guwahati, Assam relating to the killing of Sri Parag Kumar Das, Journalist and General Secretary, Manav Adhikar Sangram Samitee in front of the main gate of Assam Jatiya Vidyalaya, Rajgarh Road, Guwahati while he was coming out from the Bidyalaya with his minor son Shri Rohit Das, a student of Class-III in the broad day light on 17-05-1996 at 3 P.M. and attempts abetments and conspiracies in relation to or in connection with the aforesaid offences and any other offence/offences committed in the course of same transaction or arising out of the same fact or facts.

[No. 228/19/97-AVD-II]

HARI SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1257.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : भगवान महावीर मेडिकल रिसर्च सेन्टर
10-1-1, भगवान महावीर मार्ग, ए.सी. गार्डस,
हैदराबाद-500004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) “संवर्ग” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1676/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/ए.पी.-4/35(1)ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF
INCOME TAX (EXEMPTION)

Calcutta, the 14th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1257.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**Bhagavan Mahavir Medical Research Centre,
10-1-1, Bhagwan Mahavir Marg, A.C. Guards,
Hyderabad-500004.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1676/F. No. DG/IT(E)/CAL/AP-4/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1258.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : इकोनोमिक एण्ड सैन्टीफिक रिसर्च फाउण्डेशन,
फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग,
नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1677/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.68/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 14th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1258.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**Economic & Scientific Research Foundation,
Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1677/F. No. DG/IT(E)/CAL/ND-68/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1259.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम : **इंडियन कौंसिल फोर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशन्स ईस्ट कोर्ट, चौथी मंजिल, इंडिया हबीटेड सेन्टर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1678/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-23/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 14th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1259:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

Indian Council for Research on International Economic Relations, East Court, 4th Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1678/F. No. DG/IT(E)/CAL/ND-23/35(1)(iii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1260.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट),

(ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

सोसायटी फोर हैल्थ एलाइड रिसर्च एण्ड एजुकेशन इंडिया (शेयर इंडिया), मेदी सीटी सेन्टर, सरोवर कंप्लेक्स, सेक्रेटरिएट रोड, हैदराबाद-500004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1679/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/ए.पी.-11/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 14th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1260 .—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited

Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

Society for Health Allied Research & Education India (Share India), Medi Citi Centre, Sarovar Complex Secretariat Road, Hyderabad-500004.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1679/F. No. DG/IT(E)/CAL/AP-11/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 14 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ 1261.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” के संघर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ मैग्नेटोबायोलॉजी, 52-ए, ए.के. ब्लॉक, सातवीं मेन रोड, ऐन नगर, मद्रास-600040
यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संघर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1680/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/टी.एन.-19/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 14th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1261.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

Madras Institute of Magnetobiology, 52-A, A.K. Block, 7th Main Road, Anne Nagar, Madras-600040.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1680/F. No. DG/IT(E)/CAL/TN-19/35(1)(ii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 18 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1262.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

इंस्टीच्यूट ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट ऑफ इंडिया,
13/6, मैलेजस्टोन पनसेथ रोड, पी. ओ. गिरिनगर,
पुना-411025

यह अधिसूचना दिनांक 3-6-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1681/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम.-195/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 18th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1262.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation .

**Institute of Poultry Management of India,
13/6, Milestone, Panshet Road, P.O. Girinagar,
Pune-411025**

This notification is effective for the period from 3-6-96 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through

the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1681/F. No. DG/IT(E)/CAL/M-195/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 18 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1263.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

सोसायटी फोर कपिटल मार्केट रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट,
74, वैशाली पीतमपुरा, दिल्ली-110034

यह अधिसूचना दिनांक 29-3-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
- (1) उपर्युक्त शर्त (i) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 - (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिर्देशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1682/ एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-142/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 18th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1263.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation .

**Society for Capital Market Research & Development,
74, Vaishali, Pitampura,
Delhi-110034.**

This notification is effective for the period from 29-3-96 to 31-3-98.

- Notes :**
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1682/ F. No. DG/IT(E)/CAL/ND-142/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 18 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1264.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिर्देशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एरिगेशन एण्ड पावर, मालचा मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : (1) उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
- (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1683/एफ.सं. म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी-51/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 18th February, 1997

INCOME TAX

S. O. 1264.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Directorate of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

Central Board of Irrigation & Power, Malcha Marg,
Chanakypuri, New Delhi-110021

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1683/F. No. DG/IT(E)/CAL/ND-51/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 4 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1265.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

दि ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया,
3, रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :** (1) उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
- (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1684/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-49/कल/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 4th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1265.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road,

New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**The Tuberculosis Association of India,
3, Red Cross Road, New Delhi-110001.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1684/F. No. DG/IT(E)/ND-49/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 4 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1266.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट),

(ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी,
18/2, सतसंग विहार मार्ग, स्पेशल इण्डस्ट्रीयल एरिया,
नई दिल्ली-110067

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी : (1) उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
- (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1685/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)एन.डी.-72/कल/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 4th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1266.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited

Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**National Institute of Public Finance & Policy,
18/2, Satsang Vihar Marg, New Delhi-110067.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1685/F. No. DG/IT(E)/ND-72/CAL/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 4 फरवरी, 1997

आयकर

का. आ. 1267.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

इन्द्राप्रस्था कैंसर सोसायटी एण्ड रिसर्च सेंटर,
क्यू-5ए, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014

यह अधिसूचना दिनांक 28-9-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1686/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-133/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 4th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1267.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Indraprastha Cancer Society and Research Centre,
Q-5A, Jangpura Extn., New Delhi-110014.

This notification is effective for the period from 28-9-96 to 31-3-99.

- Notes :**
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1686/F. No. DG/IT(E)/ND-133/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 10 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1268.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

दि फाउण्डेशन फोर रिसर्च इन कम्प्यूनिटी हेल्थ,
84, ए.आर.जी. थाडानी मार्ग, वाल्मी,
बम्बे-400018

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1687/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-75/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 10 March, 1997

INCOME TAX

S.O. 1268.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**The Foundation for Research in Community Health,
84, A.R.G. Thadani Marg, Worli, Bombay-400018.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of

Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1687/F. No. DG/IT(E)/M-75/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 7 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1269.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**दि इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकलचरल इकोनोमिक्स,
46/48, ईस्प्लानेट मैनसन्स, एम.जी. रोड, बम्बे-400001**

यह अधिसूचना दिनांक 22-9-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1688/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-33/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 7 March, 1997

INCOME TAX

S.O. 1269.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**The Indian Society of Agricultural Economics,
46/48, Esplanade Mansions,
M.G. Road, Bombay-400001.**

This notification is effective for the period from 22-9-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1688/F. No. DG/IT((E)/M-33/CAL/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 7 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1270.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**महाराष्ट्र स्टेट ग्राएफ गोरोवर्स एसोसिएशन,
दराकसा भवन, ई-4, मार्केट वाई गुलटेकादी,
पुना-411037**

यह अधिसूचना दिनांक 4-4-95 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :** 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1689/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-13/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 7th March, 1997

INCOME TAX

S.O. 1270.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax

Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**Maharashtra State Grape Grower's Association,
Draksha Bhavan, E-4, Market,
Yard Gultekadi, Pune-411037.**

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-97.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1689/F No. DG/IT(E)/M-13/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 10 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1271.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**आईसी एग्रीकलचरल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाउण्डेशन,
पी.ओ. बॉक्स नं. 7602, आदर्श हाउसिंग सोसायटी
क्रास रोड, नं.-1ए मलाद (डब्ल्यू), बम्बे-400064**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1690/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम.-4/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 10th March, 1997

INCOME TAX

S.O. 1271.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary,

Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Aspec Agricultural Research & Development Foundation, P.O. Box No. 7602, Adarsh Housing Society Cross Road, No. 1, Malad (W), Bombay-400064

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1690/F. No. DG/IT(E)/M-4/CAL/35(1)(ii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 11 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1272.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट)

जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**दि कुपुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीच्यूट,
84, थिरु भीका रोड, मलापुर, मद्रास-600004**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) “संवर्ग” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1691/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/टी.एन.-41/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 11th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1272.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**The Kuppaswami Sastri Research Institute,
84, Thiru Vika Road, Mylapore, Madras-600004.**

This notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1691/F. No. DG/IT(E)/TN-41/CAL//35(1)(iii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 12 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1273.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**श्री वेंकाटेश्वरा इंस्टीच्यूट फार मेडिकल साइंसेस,
अली पीरीरोड, तिरुपति-517507**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1692/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/ए.पी.-20/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, 12th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1273.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**Sri Venkateshwara Institute for Medical Sciences,
Alipiri Road, Tirupati-517507.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

sion of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1692/F. No. DG/IT((E)/AP-20/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director,

कलकत्ता, 14 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1274.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिकी भवन”, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

बोस इंस्टीच्यूट,
93/1, ए.पी.सी. रोड, कलकत्ता-700009

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निर्देशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन

की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1693/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/डब्ल्यू. बी.-41/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 14th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1274.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Bose Institute,
93/1, A.P.C. Road, Calcutta-700009.

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

- Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1693/F. No. DG/IT(E)/WB-41/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 17 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1275.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया कार्य संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल,
वेल्लोर-632004, तमिलनाडु

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा-संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1694/एफ.सं.म.नि./आ.फ.(छूट)/कल/टी.एन.-31/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 17th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1275.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Christian Medical College & Hospital,
Vellore-632004, Tamilnadu.

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

- Notes :**
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income-Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1694/F. No. DG/IT(E)/TN-31/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 19 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1276.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर,
नंदीर गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद-380009

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है। के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1695/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/जी.-69/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 19th March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1276:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Lalbhai Dalpatbhai Bhartiya Sanskriti Vidyamandir,
Near Gujarat University, Ahmedabad-380009.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

- Notes :
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1695/F. No. DG/IT(E)G/CAL-69/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1277.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट)

जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

कमला नेहरू मैमोरियल हॉस्पिटल पद्मा कुटीर,
तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1696/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-98/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1278.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Kamala Nehru Memorial Hospital,
Padma Kutir, Teen Murti House,
New Delhi-110001.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

- Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
(2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1696/F. No. DG/IT(E)/ND-98/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1278.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

टेक्नोलॉजी इंफोरमेशन फोरकार्टींग एण्ड असेसमेंट कौंसिल
(टी.आई.एफ.ए.सी.) डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिसके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1697/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-116/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1278:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Technology Information Forecasting & Assessment Council (TIFAC) Department of Science & Technology, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016.

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1697/F. No. DG/IT(E)/ND-116/CAL//35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1279:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35, की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क), आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन

की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1698/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-44/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1279:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**The Indian Law Institute,
Bhagwandas Road, New Delhi-110001.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1698/F. No. DG/IT(E)/ND-44/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1280:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहीखांखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**एशियन एनर्जी इंस्टीट्यूट, ई-475, ग्रेटर कैलाश-II,
नई दिल्ली-110048**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1699/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-103/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1280:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax

Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Asian Energy Institute, E-475, Greater Kailash-II, New Delhi-110048.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-97.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1699/F. No. DG/IT(E)/ND-103/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1281:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

1096GI/ 97—4

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूजियमस, सेक्टर-5, ब्लॉक-जी.ए., विधान नगर, कलकत्ता-700091

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1700/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/डब्ल्यू.बी.-35/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1281:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary,

Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/ Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**National Council of Science Museums,
Sector-V, Block-GN, Bidhan Nagar,
Calcutta-700091.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1700/F. No. DG/IT(E)/WB-35/CAL/35(1)(ii)]
MUKESH KUMAR. Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1282:— सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**डायबेटीक एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहेजा हॉस्पिटल रोड,
महीम, मुम्बई-400016**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से उक्त महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1701/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम.-56/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1282:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/ Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**Diabetic Association of India, Raheja Hospital Road,
Mahim, Mumbai-400016.**

This notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1701/F. No. DG/IT(E)/M-56/CAL/35(1)(ii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 3 अप्रैल, 1997

आयकर

का. आ. 1283:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 को उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**दि मदर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च,
10, तालकाटोरा रोड, नई दिल्ली-110001**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1702/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-47/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 3rd April, 1997

INCOME TAX

S. O. 1283:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of the Organisation :

**The Mothers Institute of Research,
10, Talkatora Road, New Delhi-110001.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction

over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1702/F. No. DG/IT(E)/ND-47/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1284:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

मुलजीभाई पटेल सोसायटी फॉर रिसर्च इन नेफ्रो उरुलॉजी,
डा. विरेन्द्र देसाई रोड, नदियाद-387001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1703/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/जी.-10/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1284:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule. 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**Muljibhai Patel Society for Research in Nephro-Urology, Dr. Virendra Desai Road,
Nadiad-387001.**

This notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

- Notes :**
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1703/F. No. DG/IT(E)/G-10/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1285:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35

की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

दि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनोमी एण्ड प्लानेटोरियम साइंसेस,
बिरला बिल्डिंग, 9/1, आर.एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1704/एफ.से.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/डब्ल्यू.बी.-3/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1285:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research,

'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;

- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

The Birla Institute of Astronomy & Planetarium Sciences, Birla Building, 9/1, R.N. Mukherji Road, Calcutta-700001.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :**
- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
 - (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1704/F. No. DG/IT(E)/WB-3/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1286:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च, किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

सर हरकिशन दास नौरोत्तम दास मेडिकल रिसर्च सोसायटी,
राजा राम मोहन राय रोड, बम्बई-400004

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-97 से 31-3-2000 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1705/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम-25/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1286:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of

audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Sir Hurkisandas Nurrotumdas Medical Research Society, Raja Rammohan Roy Road, Bombay-400004.

This notification is effective for the period from 1-4-97 to 31-3-2000.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1705/F. No. DG/IT(E)/M-25/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1287:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा,
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

दि केलकर एजुकेशन ट्रस्ट, सी/ओ.एस.एच. केलकर एण्ड
कम्पनी लिमिटेड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
मुलुन्द (वेस्ट), बम्बई-80

यह अधिसूचना दिनांक 12-3-97 से 31-3-98 तक की अवधि
के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू
नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की
अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर
निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता
है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट),
कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन
की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की
छः प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1706/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एम.-177/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1287:—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

The Kelkar Education Trust, C/o S.H. Kelkar & Co.
Ltd., Lal Bahadur Shastri Marg, Mulund (West),
Bombay-80.

This notification is effective for the period from 12-3-97 to 31-3-98.

- Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1706/F. No. DG/IT(E)/M-177/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1288:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

प्रोसेस इंजीनियरिंग डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट,
ए.डी.-161, साल्ट लेक सिटी, सेक्टर-1, कलकत्ता-700064

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1707/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/डब्ल्यू.बी.-36/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1288.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

Process Engineering Design & Development Institute, AD-161, Salt Lake City, Sector-J, Calcutta-700064.

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of

Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1707/F. No. DG/IT(E)/WB-36/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1289.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**कुन्दालीनी रिसर्च एसोसिएशन इंटरनेशनल (इंडियन चापटर)
15, इंस्टीट्यूशनल एरीया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रतियां विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1708/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-119/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1289.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**Kundalini Research Association International
(Indian Chapter), 15, Institutional Area,
Lodhi Road, New Delhi-110003.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1708/F. No. DG/IT(E)/ND-119/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1290.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**आल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस,
अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (i) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को छः प्रतियां प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1709/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-26/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1290.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of

section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar, New Delhi-110029.**

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1709/F. No. DG/IT(E)/ND-26/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1291.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्थान" के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ सैकोमेट्री, एवरशीप भवन,
दूसरी से पांचवी मंजिल, 117, बी.टी रोड, कलकत्ता-700035**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1710/एफ.से.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/डब्ल्यू.बी.-7/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1291.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary,

Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**Indian Institute of Psychometry,
Evergreen Plaza, 2nd to 5th Floor,
117, B.T. Road, Calcutta-700035.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1710/F. No. DG/IT(E)WB-7/CAL//35(1)(iii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1292.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**नेशनल कॉसिल ऑफ अप्लाइड एकोनॉमिक रिसर्च,
11-इन्द्राप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-96 से 31-3-99 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

- टिप्पणी :**
1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
 2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1711/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/कल/एन.डी.-41/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1292.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation :

**National Council of Applied Economic Research,
11-Indraprastha Estate, New Delhi-110002.**

This notification is effective for the period from 1-4-96 to 31-3-99.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1711/F. No DG/IT(E)/ND-41/CAL/35(1)(iii)]
MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1293.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

**सेन्टर फोर वूमिन्स डेवलपमेंट स्टडीज,
25, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001**

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-98 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :

1. उपर्युक्त शर्त (i) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।
2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1712/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एन.डी.-53/35(1)(iii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1293.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year;
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation

**Centre for Women's Development Studies,
25, Bhai Vir Singh Marg, New Delhi-110001.**

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-98.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General

of Income Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1712/F. No. DG/IT(E)/ND-53/35(1)(iii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

कलकत्ता, 31 मार्च, 1997

आयकर

का. आ. 1294.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्थान” के संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिकी भवन”, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में वित्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च किया गया कार्य संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय के हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम :

इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इंडियन सेक्शन,
आई.एम.ए. हाउस, 16 केशवराव खादी मार्ग, हाजी अली,
बम्बे-400034

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-97 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की छः प्रतियां सचिव, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1713/एफ.सं.म.नि./आ.क.(छूट)/एम.-47/कल/35(1)(ii)]

मुकेश कुमार, अपर निदेशक

Calcutta, the 31st March, 1997

INCOME TAX

S. O. 1294.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule, 6 of the Income-Tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Institution” subject to the following conditions :—

- (i) The organisation shall maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It shall furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, ‘Technology Bhawan’, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year,
- (iii) It shall submit to the (a) Director General of Income-Tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income Tax/Director of Income-Tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income & Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of section 35 of Income Tax Act, 1961.

Name of Organisation

International College of Surgeons,
Indian Section, I.M.A. House, 16, Keshavrao
Khady Marg, Haji Ali, Bombay-400034.

This notification is effective for the period from 1-4-95 to 31-3-97.

- Notes :** (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicates and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-Tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-Tax/Director of Income-Tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1713/F. No. DG/IT(E)/M-47/CAL/35(1)(ii)]

MUKESH KUMAR, Addl. Director

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 मई, 1997

का.आ. 1295.—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 26 की उप धारा (2क) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (गक) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा स्टेट बैंक आफ मैसूर, नं. 61, सेन बिल्डिंग, अशोक रोड, मैसूर में सहायक प्रधान रोकड़िया श्री एच. एस. नन्जुन्दास्वामी को दिनांक 2 मई, 1997 से 1 मई 2000 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए या उनके स्टेट बैंक आफ मैसूर में कर्मचारी रहने तक, जो भी पहले हो, स्टेट बैंक आफ मैसूर के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 15/4/96-आई आर]

डा. परमजीत सिंह सिद्धू, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 1st May, 1997

S.O. 1295.—In pursuance of clause (ca) of Sub-section (1) of Section 25 read with sub-section (2A) of Section 26 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), The Central Government hereby appoints Shri H.S. Nanjundaswamy, Asstt. Head Cashier, State Bank of Mysore, No. 61, Main Building, Ashok Road, Mysore as director on the Board of State Bank of Mysore for a period of three years with effect from 2nd May, 1997 to 1st May, 2000 or until he ceases to be an employee of State Bank of Mysore whichever is earlier.

[F.No. 15/4/96-IR]

DR. PARAMJIT SINGH SIDHU, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का.आ. 1296.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्या 4170, 4172, 4174, 4176, 4177, 4178, 4181, 4183 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2990 ता. 26 अक्टूबर, 1996 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने घोषित किया कि उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया गया है कि सरकारी राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रण संबंधी कुछ त्रुटियाँ हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

- पृष्ठ संख्या 4170:— गाँव घोरादाहा के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. '2343' के स्थान पर '2341' पढ़ें। प्लॉट सं. 8250 के सामने स्तम्भ 5 में '6' के स्थान पर '0' पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4172:— गाँव घोरादाहा के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 7349 के बाद एवं प्लॉट सं. 7335 के पहले प्लॉट सं. "7350" पढ़ें, स्तम्भ 4 में "0" पढ़ें स्तम्भ 5 में "1" पढ़ें, स्तम्भ 6 में "68" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4174:— गाँव हीरापुर के प्लॉट सं. 554 के सामने स्तम्भ 5 में "4" के स्थान पर "5" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4176:— गाँव रामनगर के प्लॉट सं. 230 के सामने स्तम्भ 5 में "7" के स्थान पर "1" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4177:— गाँव कृष्णनगर के प्लॉट सं. 154 के सामने स्तम्भ 5 में "1" के स्थान पर "3" पढ़ें।
- गाँव गोरान मंदरान के प्लॉट सं. 94 के सामने स्तम्भ 4 में "9" के स्थान पर "0" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4178:— गाँव गौरान के प्लॉट सं. 304 के सामने स्तम्भ 6 में "11" पढ़ें ;
- गाँव सीतलपुर के प्लॉट सं. 1326 के सामने स्तम्भ 6 में "12" के स्थान पर "92" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4181:— गाँव अमानपुर के प्लॉट सं. 345 के सामने स्तम्भ 4 में "9" के स्थान पर "0" पढ़ें।
- पृष्ठ संख्या 4183:— गाँव कासीगोरे के प्लॉट सं. 285 के सामने स्तम्भ 6 में "11" के स्थान पर "1" पढ़ें; प्लॉट सं. 94 के सामने स्तम्भ 5 में "10" के स्थान पर "0" पढ़ें।

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लिंगमें से मुक्त होकर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

[सं. आर. 31015/1/96ओ.आर-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1296.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2990, dated the 24th October, 1996, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section

(ii), at pages 4185 to 4195, issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petroleum should be acquired;

And, whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of the printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Official Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the aforesaid notifications as follows:—

at page 4187, in Village Ramchandrapur, in column 3, after Plot No. 2417, for plot No. "2410" read plot No. "2415".

at page 4189, in Village Ramnagar, against Plot No. 541, in column 6, for "87" read "78".

at page 4190, in Village Bhandarhati, against plot No. 393, in column 6, read "1".

at page 4191, in Village Selalpur, against plot No. 1163, in column 6, for "54" read "45".

at page 4193, in column 1, for Village "Walia" read "Valia".

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest free from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited.

[No. R-31015/1/96-OR-1]

K. C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1297.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्या 3432, 3433 और 3434 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2626, ता. 2 सितम्बर, 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि सरकारी राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण संबंधी कुछ गलतियां हो गई हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है:—

पृष्ठ संख्या 3433:—

गाँव घग्गा बासुदेबपुर के बाद, गाँव ख्वाजपुरा (जे. एल. सं.-32) से "पुलिस थाना : पंचला, जिला: हावड़ा, राज्य : पश्चिमी बंगाल" शुरू होगा।

गाँव ख्वाजपुरा के प्लॉट सं. 423 के सामने स्तम्भ 6 में "644" के स्थान पर "64" पढ़ें; प्लॉट सं. 424 के सामने स्तम्भ 6 में "2" के स्थान पर "24" पढ़ें; प्लॉट सं. 428 के सामने स्तम्भ 6 में "4" के स्थान पर "40" पढ़ें; प्लॉट सं. 435 के सामने स्तम्भ 4 में "9" के स्थान पर "0" पढ़ें; प्लॉट सं. 644 के सामने स्तम्भ 6 में "2" पढ़ें; प्लॉट सं. 645 के सामने स्तम्भ 6 में "2" के स्थान पर "20" पढ़ें; प्लॉट सं. 650 के सामने स्तम्भ 6 में "2" के स्थान पर "20" पढ़ें;

गाँव साहपुर के प्लॉट सं. 551 के सामने स्तम्भ 6 में "2" के स्थान पर "20" पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 3434 :-

गाँव साहपुर के बाद, गाँव नालपुर (जे. एल. सं.-12) से पहले "पुलिस थाना संकरेल जिला: हावड़ा, राज्य: पश्चिमी बंगाल" शुरू होगा;

गाँव रघुदेवबाती के बाद, गाँव चक्रमधु (जे. एल. सं.-11) से "पुलिस थाना: बौरिया जिला: हावड़ा, राज्य: पश्चिमी बंगाल" शुरू होगा।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किये जाने के इक्कीस दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर उपयोग के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया बज बज पाइपलाइन परियोजना, पोस्ट-हल्दिया रिफाइनरी जिला मिदनापुर पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:— इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बाबत ही उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार इक्कीस दिन की उक्त अवधि उम्र तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[सं. आर-31015/6/96-ओ. आर -1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1297.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2626, dated the 2nd September, 1996, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), at pages 3435 to 3437, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification;

And, whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of the printing nature have occurred in the publication of the said notification in the official Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the said notifications as follows:-

at page 3436,-

- (i) in column 1 for village "Gharbhanga Baiudebpur - contd." read "Gharbhanga Basudebpur - Contd.";
- (ii) after village "Gharbhanga Basudebpur" so amended and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"Police Station: Panchla District: Howrah State: West Bengal";

at page 3437,-

- (i) after village Khayjapur and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—
"Police Station: Sankrail District: Howrah State: West Bengal";
- (ii) after village Raghudebbati and entries relating thereto, the following shall be inserted namely :—
"Police Station: Bauria District: Howrah State: West Bengal";
- (iii) in column 1 for village "Chahmadhu" read "Chakmadhu";
- (iv) in village Khas Khamar against plot No. 99, in column 6, for "No" read "20"; in column 3, after plot No. 104, for plot No. "107" read "109".

Any person interested in any land in respect of which the above amendments have been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right of user in or over such land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, to Shri Biswanath Bose, Competent

Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia—Budge Budge Pipeline Project, Post Office—Haldia Refinery, District—Midnapur (West Bengal).

Explanation—In respect of the lands, plot numbers and areas amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, starts running from the date of notification is made available to the public after publication in the official Gazette.

[No. R-31015/6/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल 1997

का. आ. 1298.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्या 4105, 4106, 4107, 4108, 4109 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2986, ता. 26 अक्टूबर, 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि सरकारी राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण संबंधी कुछ गलतियाँ हो गई हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है :—

पृष्ठ संख्या 4105 :— गाँव भडा के प्लॉट सं. 2601 के सामने स्तम्भ 6 में "65" पढ़ें, प्लॉट सं. 2570 के सामने स्तम्भ 6 में "9" पढ़ें, प्लॉट सं. 2568 के सामने स्तम्भ 6 में "5" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4106 :— गाँव बेलारी के प्लॉट सं. 3850 के सामने स्तम्भ 5 में "0" पढ़ें, स्तम्भ 6 में "94" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4107 :— गाँव बेलग्राम के प्लॉट सं. 3951 के सामने स्तम्भ 4 में "0" पढ़ें, स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 3941 के बाद, प्लॉट सं. "3916" के स्थान पर "3915" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4108 :— गाँव नाओडा के प्लॉट सं. 1195 के सामने स्तम्भ 6 में "32" के स्थान पर "23" पढ़ें ;

पृष्ठ संख्या 4109 :— गाँव "गुसकारा" के स्थान पर "गुसकाग" पढ़ें ;

गाँव गुसकाग के प्लॉट सं. 3347 के सामने स्तम्भ 1 में गाँव "गुसकारा-जारी" के स्थान पर "गुसकाग-जारी" पढ़ें; प्लॉट सं. 3368 के सामने स्तम्भ 6 में "99" के स्थान पर "9" पढ़ें; प्लॉट

सं. 3605 के सामने स्तम्भ 6 में "55" के स्थान पर "5" पढ़ें।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किये जाने के इक्कीस दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया बरौनी कूड पाइपलाइन परियोजना, पोस्ट-खंजनचक, बासुदेवपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :— इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बाबत ही उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार इक्कीस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है।

[सं. आर-31015/9/96-ओ. आर-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1298.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2986, dated the 26th October, 1996, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), at pages 4110 to 4114, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention of acquire the land specified in the Schedule appended to that notification;

And, whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of the printing nature have occurred in the publication of the said notification in the Official Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the said Act, the Central Government hereby amends the Schedule appended to the aforesaid notification as follows :—

at page 4110—in village Bhada, against plot No. 3014, in column 6, for "14" read "1";

at page 4111—in village Belari, in column 3, after plot No. 3850, for plot No. "2870" read "3870";

at page 4112, in village Belgram,—

- (i) against plot No. 4036 in column 5 insert "7";
- (ii) against plot No. 4022 in column 6 for "37" read "39";
- (iii) against plot No. 3915 in column 5 for "1" read "2" and in column 6 for "29" read "4";
- (iv) after plot No. 3919, in column 3 for plot No. "3720" read "3920";

(v) against plot No. 3849 in column 6 for "67" read "69";

(vi) against plot No. 1566, in column 6 insert "70";
at page No. 4113, in village Shibda, against plot No.—

(i) 2151, in column 6, for "3" read "35";

(ii) 2155, in column 6, for "1" read "12";

Any person interested in any land in respect of which the above amendments have been issued, may within twenty one days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right of user in or over such land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, to Shri Biswanath Bose, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Crude Pipeline Project, Post Office—Khanjanchak, Basudebpur, District—Midnapur (West Bengal).

Explanation—In respect of the lands, plot numbers and areas amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, starts running from the date of notification is made available to the public after publication in the official Gazette.

[No. R-31015/9/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1299.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्या 4114 से 4131 पर और पृष्ठ संख्या 4143 से 4157 पर प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2987 और 2988, ता. 26 अक्टूबर, 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि सरकारी राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण संबंधी कुछ गलतियां हो गई हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है :—

पृष्ठ संख्या 4114 :—'पुलिस थाना : सुताद्याता' के स्थान पर 'पुलिस थाना : सुताहाता' पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 4116 :—गांव किश्मत शिवरामनगर के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1309 के बाद, प्लॉट सं. "3308" के स्थान पर "1308" पढ़ें।

पृष्ठ संख्या 4119 :—गांव सपुआ के प्लॉट सं. 561 के सामने स्तम्भ 6 में "4" के स्थान पर "43" पढ़ें।

पुलिस थाना : महिषादल के सामने "जिला :
मिददापुर" के स्थान पर "जिला मिदनापुर" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4120 :—गांव कालीका कुन्डू के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 2182 के बाद, प्लॉट सं. "2133" के स्थान पर "2183" पढ़ें; प्लॉट सं. 1911 के सामने स्तम्भ 6 में "21" के स्थान पर "26" पढ़ें; प्लॉट सं. 1872 के सामने स्तम्भ 6 में "26" के स्थान पर "21" पढ़ें; प्लॉट सं. 206 के सामने स्तम्भ 4 में "6" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

गांव लाख्या के प्लॉट सं. 4026 के सामने स्तम्भ 4 में "2" के स्थान पर "0" पढ़ें; प्लॉट सं. 4013 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4121 :—गांव लाख्या के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 3768 के बाद, प्लॉट सं. "3269" के स्थान पर "3769" पढ़ें ;
गांव चानपी के प्लॉट सं. 1948 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

गांव झाऊपतरा के प्लॉट सं. "888" के सामने स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4122 :—गांव झाऊपतरा के प्लॉट सं. 209 के सामने स्तम्भ 6 में "45" के स्थान पर "40" पढ़ें ; प्लॉट सं. 94 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

गांव काकुरदाहा के प्लॉट सं. 215 के सामने स्तम्भ 6 में "25" के स्थान पर "20" पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 215 के बाद, प्लॉट सं. "214" के स्थान पर "219" पढ़ें ; प्लॉट सं. 57 के सामने स्तम्भ 4 में "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4123 :—गांव बागदा के प्लॉट सं. 1136 के सामने स्तम्भ 6 में "83" के स्थान पर "88" पढ़ें; प्लॉट सं. 1096 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 1104 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 1066 के सामने स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 1064 के सामने स्तम्भ 5 में "2" के स्थान पर "1" पढ़ें ; स्तम्भ 6 में "83" के स्थान पर "62" पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1064 के बाद, प्लॉट सं. "1093" के स्थान पर "1063" पढ़ें, स्तम्भ 5 में "4" के स्थान पर "2" पढ़ें, स्तम्भ 6 में "82" के स्थान पर "83" पढ़ें; प्लॉट सं. 1268 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें; प्लॉट सं. 1055 के सामने स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

गांव कंचनपुर के प्लॉट सं. 177 के सामने स्तम्भ 6 में "31" के स्थान पर "81" पढ़ें ; प्लॉट सं. 176 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें; प्लॉट सं. 181 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान

पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 89 के सामने 6 में "31" के स्थान पर "81" पढ़ें ; प्लॉट सं. 237 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें, स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 286 के पहले, प्लॉट सं. "348" के स्थान पर "349" पढ़ें ; प्लॉट सं. 343 के सामने स्तम्भ 6 में "25" के स्थान पर "20" पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 321 के बाद, प्लॉट सं. "922" के स्थान पर "322" पढ़ें ; प्लॉट सं. 324 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "1" पढ़ें ;

गांव राजारामपुर के प्लॉट सं. 1515 के सामने स्तम्भ 6 में "00" के स्थान पर "20" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4124 :—गांव राजारामपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1468 के बाद प्लॉट सं. "2893" के स्थान पर "2893" पढ़ें ;

गांव माधवपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 2291 के बाद, प्लॉट सं. "2384" के स्थान पर "2284" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4126 :—गांव नाईकुन्डी के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 437 के बाद, प्लॉट सं. "425" के स्थान पर "435" पढ़ें ;

गांव कुमारारा के प्लॉट सं. 860 के सामने स्तम्भ 4 में "50" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 1055 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "6" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4127 :—गांव कुमारारा के प्लॉट सं. 758 के सामने 6 में "6" के स्थान पर "62" पढ़ें ;

गांव जसनान के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 66 के बाद, प्लॉट सं. "6" के स्थान पर "67" पढ़ें ; प्लॉट सं. 68 के बाद, प्लॉट सं. "6" के स्थान पर "69" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4128 :—गांव कोलसार के प्लॉट सं. 985 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "2" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4129 :—गांव दक्षिण श्रीकृष्णापुर के स्तम्भ 2 में जे एल सं. "50" के स्थान पर "59" पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 793 के बाद, प्लॉट सं. "992" के स्थान पर "792" पढ़ें ;

गांव पुयदा के प्लॉट सं. 2171 के सामने स्तम्भ 6 में "43" के स्थान पर "41" पढ़ें ; प्लॉट सं. 2155 के सामने स्तम्भ 6 में "242" के स्थान पर "24" पढ़ें ; प्लॉट सं. 2153 के सामने स्तम्भ 6 में "6" के स्थान पर "62" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4130 :—गांव तारागेरिया के प्लॉट सं. 70 के सामने स्तम्भ 6 में "18" के स्थान पर "81" पढ़ें ;

गांव गुरिया के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 961 के बाद, प्लॉट सं. "963" के स्थान पर "968" पढ़ें ;

प्लॉट सं. 659 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 624 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "1" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4145 :—गांव दक्षिण उसतपुर के प्लॉट सं. 1238 के सामने स्तम्भ 5 में "६" के स्थान पर "9" पढ़ें, स्तम्भ 6 में "61" के स्थान पर "31" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4146 :—गांव बालीकलुआ के प्लॉट सं. 393 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 364 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें, स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4147 :—गांव नरसिंह कलुआ के प्लॉट सं. 524 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 515 के सामने स्तम्भ 4 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

गांव अमगेछया के प्लॉट सं. 413 के बाद प्लॉट सं. 432 के सामने स्तम्भ 1 में गांव "बालीकलुआ-जारी" के स्थान पर "अमगेछया-जारी" पढ़ें ;

गांव बनीचार के प्लॉट सं. 764 के सामने स्तम्भ 4 में "4" के स्थान पर "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4148 :—गांव राधाबल्लवपुर के प्लॉट सं. 536 के सामने स्तम्भ 4 में "3" के स्थान पर "0" पढ़ें ;

पृष्ठ संख्या 4149 :—गांव दाहारपुर के प्लॉट सं. 84 के सामने स्तम्भ 6 में "45" के स्थान पर "5" पढ़ें ; प्लॉट सं. 32 के सामने स्तम्भ 6 में "8" के स्थान पर "87" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4150 :—गांव कापाशबेरे के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1538 के बाद, प्लॉट सं. "1636" के स्थान पर "1536" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4151 :—गांव धारिण्डा के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1872 के बाद, प्लॉट सं. "2871" के स्थान पर "1871" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4152 :—गांव राजगोडा के सामने स्तम्भ सं. 3 में प्लॉट सं. 308 के सामने स्तम्भ सं. 1 में पु. था. पंसकूश के स्थान पर पु. था. "पंसकुरा" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4153 :—गांव शारदाबसन के प्लॉट सं. 243 के सामने स्तम्भ 4 में "4" के स्थान पर "0" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4154 :—गांव नंदाईगजन के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 632 के बाद, प्लॉट सं. "1158" के स्थान पर "1358" पढ़ें । प्लॉट सं. 1077 के बाद, प्लॉट सं. "992" के स्थान पर "902" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4155 :—गांव देरियाचक के प्लॉट सं. 1234 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "5" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4156 :—गांव देरियाचक के प्लॉट सं. 2159 के सामने स्तम्भ 1 में "चैनपुर" के स्थान पर "देरियाचक-जारी"

पढ़ें, स्तम्भ 2 में जे एल सं. "321" के स्थान पर "318" पढ़ें ।

गांव चैनपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट सं. 1532 के बाद, प्लॉट सं. 1529 के सामने स्तम्भ 1 में "दारिमाचक" के स्थान पर "चैनपुर-जारी" पढ़ें, स्तम्भ 2 में जे एल सं. "318" के स्थान पर "321" पढ़ें ।

पृष्ठ संख्या 4157 :—गांव बहरापोटा के प्लॉट सं. 409 के सामने स्तम्भ 6 में "45" के स्थान पर "40" पढ़ें ; प्लॉट सं. 553 के सामने स्तम्भ 5 में "5" के स्थान पर "0" पढ़ें ; प्लॉट सं. 421 के सामने स्तम्भ 5 में "0" के स्थान पर "4" पढ़ें ; प्लॉट सं. 431 के सामने स्तम्भ 1 में गांव "हरापोटा" के स्थान पर "बहरापोटा-जारी" पढ़ें ।

ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किये जाने के इक्कीस दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या उस पर उपयोग के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री बिश्वनाथ बोस, सक्षम प्रार्थिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया बरीनी कूड पाइपलाइन परियोजना, पोस्ट-खंजनचक, बासुदेवपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बाबत ही उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार इक्कीस दिन की उक्त अवधि उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् जनता को उपलब्ध करा दी जाती है ।

[सं. आर- 31015/10/96-ओ. आर -1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1299.—Whereas by the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2987 and 2988, dated the 26th October, 1996, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), at pages 4131 to 4143 and 4157 to 4167, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government gave notice of its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification;

And, whereas, it has been brought to the notice of the Central Government that certain errors of the printing nature have occurred in the publication of the said notification in the official Gazette;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Gov-

ernment hereby amends the schedule appended to the aforesaid notifications as follows :—

at page 4132, in column 1 for village “Teutiberia (contd.)” read (Tentulberia (contd.)); in 0 amended village Tentulberia against Plot No. 269, in column 5, for “0” read “1”.

at page 4133 in Village Manoharpur, against Plot No. 357, in column 5, for “0” read “2”; in column 3, after Plot No. 1782, for Plot No. “1724” read “1824”;

in Village Gorankhali against Plot No. 484, in column 5, for “9” read “8”.

at page 4134, in Village Gorankhali, in column 3, after Plot No. 540 read Plot No. “548”, in column 4 read “0”, in column 5 read “0”, in column 6 read “20”.

at page 4140, in Village Naikundi, against Plot No. 1, in column 4, for “1” read “0”.

at page 4158, in village Nilkunthia, against Plot No. 962, in column 6, for “438” read “43”.

at page 4159, in Village Dakshin Usatpur, against Plot No. 1583, in column 6, for “2” read “22”; against Plot No. 1588, in column 6, for “2” read “63”; against Plot No. 1587, in column 6, for “4” read “43”; against Plot No. 1775, in column 6, for “3” read “5”;

in Village Ramkalua, in column 2, for Jurisdiction List No. “79” read “97”;

in column 1, for Village “Baklialua” read “Balikalua”.

at page 4160, in village Balikalua, against Plot No. 364, in column 6, for “64” read “20”; in column 3, after Plot No. 350, for Plot No. “347” read “349”; in column 3, before Plot No. 158, for Plot No. “273” read “293”;

in Village Banhichar, against Plot No. 770, in column 6, for “0” read “2”.

at page No. 4161, in column 1 for Village “Bhubaneshwar” read “Bhubaneshwarpur”, in column 2 for Jurisdiction List No. “46” read “146”;

in Village Barpadumbasan, against Plot No. 206, in column 6, for “88” read “81”; in column 3, after Plot No. 195 and before Plot No. 204, read Plot No. “194”, in column 4 read “0”, in column 5 read “0”, in column 6 read “20”.

at page 4163, in column 1 for Village “Kapasphere” read “Kapasbere”.

at page 4166, in column 1 for Village “Nandaigazam” read “Bangalpur”; in Village Bangalpur against Plot No. 1398, in column 4, for “3” read “0”;

in Village Chainpur, against Plot No. 1528, in column 6, for “14” read “41”.

at page No. 4167, in column 1, for Village “Chainpar” read “Chainpur”; for “Ukhrepara” read “Ukhrapara”; for “Baharpeta” read “Baharpota”.

Any person interested in any land in respect of which the above amendments have been issued, may within twenty

one days of the issue of this notification, object to the acquisition of the whole or any part of the said land or any right in or over such right of user in the said land in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, to Shri Biswanath Bose, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Haldia—Barauni Crude Pipeline Project, Post Office—Khanjanchak, Basudevpur, District—Midnapur (West Bengal).

Explanation—in respect of the lands, plot numbers and areas amended through this notification only, the said period of twenty one days in terms of sub-section (1) of section 5 of the said Act, starts running from the date of notification is made available to the public after publication in the official Gazette.

[No. R-31015/10/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1997

का.आ. 1300.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भी प्राधिकृत करती है,—

अनुसूची

प्राधिकारी का नाम और पता	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)
मो. रबिऊल कामाल (एस.आर.ओ.-II भूमि अर्जन अधिकारी, पश्चिमी बंगाल राज्य से प्रतिनियुक्ति पर) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हल्दिया—बरौनी क्रूड पाइपलाइन परियोजना, कच्नारी पट्टी, बोलपुर-731204, जिला बीरभूम, पश्चिमी बंगाल।	पश्चिमी बंगाल राज्य और बिहार राज्य

[सं. आर.-31015/6/97-ओ. आर.-I]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 12 May, 1997

S.O. 1300.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby also authorise the authority mentioned in

column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act, in respect of the areas mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule.—

SCHEDULE

Name and address of the authority Area of Jurisdiction

(1)	(2)
Md. Rabiul Kamal (S.R.O-II Land Acquisition Officer, on deputation from the Government of West Bengal) Indian Oil Corporation Limited, Haldia-Barauni Crude Oil Pipeline Project, Kachhari Patty, Bolpur-731204, District-Birbhum, West Bengal.	The State of West Bengal and the State of Bihar.

[No. R-31015/6/97-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मई, 1997

का. आ. 1301.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 569, तारीख 26-2-1994 तथा का.आ. 3251, तारीख 16-12-1995 का संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, डाक घर - हल्दिया रिफाइनरी, जिला—मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल, शब्दों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

डाक घर - खंजनचक, बासुदेवपुर,
जिला - मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल

[सं. आर-31015/52/93-ओ. आर.-I]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 12th May, 1997

S.O. 1301.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers S.O. 569 dated 26-02-1994 and S.O. 3251 dated 16-12-1995, namely:—

In the said notifications, for the letters and words “P.O.-Haldia Refinery, District—Midnapur, West Bengal”, the following shall respectively be substituted, namely:—

“Post Office - Khanjanchak, Basudevpur, District - Midnapur, West Bengal”.

[No. R-31015/52/93 - OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1997

का.आ. 1302.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3975 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) का मद्रास में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी, नं. 6, 3 मैन रोड, इंदिरा नगर, मद्रास-600020 को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 22-1-1997 से प्रभावी से और तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा मान्यता देती है, अर्थात्:—

- (1) मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी, निर्यात निरीक्षण परिपद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (2) मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5 (12)/97-ई.आई.एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 30th April, 1997

S.O. 1302.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years w.e. f. 22-1-1997. M/s Essen & Company, No. 6, III Main Road, Indira Nagar, Madras-600020, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) specified in schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3975 dated 20-12-1965 prior to export at Madras, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. Essen & Company, shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the

method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-II) (Inspection) Rules, 1965;

- (ii) that M/s. Essen & Company, in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5(12)/97-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1997

का.आ. 1303.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3978 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-2) का मद्रास में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी, नं. 6, 3 मेन रोड, इंदिरा नगर, मद्रास-600020 को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 22-1-1997 से प्रभावी से और तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा मान्यता देती है, अर्थात्:—

- (1) मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी, निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-2) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (2) मैसर्स एस्सन एण्ड कम्पनी इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5 (12)/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 30th April, 1997

S.O. 1303.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years w.e. f. 22-1-1997. M/s Essen & Company, No. 6, III Main Road, Indira Nagar, Madras-600020, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-II) specified in schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3978 dated 20-12-1965 prior to export at Madras, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. Essen & Company, shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export

Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-II) (Inspection) Rules, 1965;

- (ii) that M/s. Essen & Company, in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[F. No. 5(12)/97-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1997

का.आ. 1304.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-1) अर्थात् कच्चा लोहा का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स सुपरिन्टेन्डेंस कम्पनी आफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, 138 अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास को एक अधिकरण के रूप में 22-1-1997 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा मान्यता देती है, अर्थात्:—

- (1) मैसर्स सुपरिन्टेन्डेंस आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, मद्रास निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे कि वह खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-1) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सके।
- (2) मैसर्स सुपरिन्टेन्डेंस कम्पनी आफ इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, मद्रास इस अधिसूचना के अधीन अपने कार्यों के अनुपालन में ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5 (11)/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 30th April, 1997

S.O. 1304.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises, for a further period of three years w.e. f. 22-1-1997. M/s Superintendence Co., of India (P) Ltd., 138, Angappa Naicken Street, Madras, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) namely Iron Ore, prior to export, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. Superintendence Co. of India (P) Ltd., Madras shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection

followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores (Group-I) (Inspection) Rules, 1965;

- (ii) that M/s. Superintendence Co. of India (P) Ltd., Madras in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5(11)/97-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1997

का.आ. 1305.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3975 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची के अनुसार खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) अर्थात् कच्चे लोहे का विशाखापत्तनम् में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स सुपरिटेण्डेंस कम्पनी आफ इंडिया (प्रा.) लि. 24/1/22-ए, थोम्पसन स्ट्रीट, विशाखापत्तनम्-530001 को एक अधिकरण के रूप में 29 जनवरी, 1997 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा मान्यता देती है, अर्थात्:—

- (1) मैसर्स सुपरिटेण्डेंस कं. आफ इंडिया (प्रा.) लि., निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगी ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (2) मैसर्स सुपरिटेण्डेंस कं. आफ इंडिया (प्रा.) लि. इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5 (13)/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 30th April, 1997

S.O. 1305.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 29th January, 1997, M/s Superintendence Co. of India (P) Ltd., 24/1/22-A, Thompson Street, Visakhapatnam-530001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) namely Iron ore specified in schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3975 dated 20-12-1965 prior to export at Visakhapatnam, subject to the following conditions, namely:—

- (i) that M/s. Superintendence Co. of India (P) Ltd., shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-I) (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) that M/s. superintendence Co. of India (P) Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[F. No. 5(13)/97-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1997

का.आ. 1306.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) अर्थात् कच्चे अयस्क का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स इंसपेक्शन एण्ड टेस्टिंग कं. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड 24-1-25 थोम्पसन स्ट्रीट, विशाखापत्तनम्-530001 को 8-1-1997 से और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्वारा मान्यता देती है:

- (1) मैसर्स इंसपेक्शन एण्ड टेस्टिंग कं. (इंडिया) प्रा. लि. निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (2) मैसर्स इंसपेक्शन एण्ड टेस्टिंग कं. (इंडिया) प्रा. लि. अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगी जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5 (14)/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 30th April, 1997

S.O. 1306.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 8-1-97, M/s Inspection & Testing Co. (India) Pvt. Ltd., 24-1-25, Thompson Street, Visakhapatnam-530001 as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) namely Iron Ore, prior to export, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. Inspection & Testing Co. (India) Pvt Ltd., shall give adequate facilities to the Officers

nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores (Group-I) (Inspection) Rules, 1965;

- (ii) that M/s. Inspection & Testing Co. (India) Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5(14)/97-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 5 मई, 1997

का.आ. 1307.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की क्रमशः अधिसूचना सं. का. आ. 3975 तारीख 20-12-1965 तथा सं. का. आ. 3978 तारीख 20-12-1965 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I तथा ग्रुप-II) का मद्रास में निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एम.एल.एम. बिल्डिंग 5, वालाज्ञा रोड, मद्रास-600002 पर स्थित मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. को 18-5-1997 से और आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन पदद्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :-

- (i) मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I तथा II) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (ii) मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5/8/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कु.पारी सुमा सुब्बान्णा, निदेशक

New Delhi, the 5th May 1997

S.O. 1307.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years from 18th May Nineteen hundred ninety seven M/s J.B. Boda Surveyors Pvt. Ltd. located at M.L. M. Building, 5, Wallajah Road, Madras - 600 002, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Groups-I & II) specified in schedule annexed to Ministry of Commerce Notification No. S.O. 3975

dated 20-12-1965 and No.S.O. 3978 dated 20-12-1965 respectively prior to export at Madras, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. J.B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Groups-I & II) (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/8/97-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 6 मई, 1997

का.आ. 1308.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. रघु बिल्डिंग, पहली मंजिल, उर्बा स्टोर्स, मंगलौर-575006 जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मैकर भवन नं. 1, सं. विठ्ठल दास ठाकरसी मार्ग, बम्बई-400020 में स्थित है को 8-3-1997 से और आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है जो कि निम्न शर्तों के अधीन होगा, अर्थात् :-

- (i) मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-I) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र दिया जा सके।
- (ii) मैसर्स जे.बी.बोडा सर्वेयर्स प्रा.लि. इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

अनुसूची

- (i) कच्चा लोहा;
- (ii) कच्चा मैंगनीज, मैंगनीज डायक्साइड को छोड़कर।

[फा. सं. 5/9/97-ई.आई. एण्ड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बान्णा, निदेशक

New Delhi, the 6th May, 1997

S.O. 1308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises for a further period of three years w.e.f. 8-3-1997, M/s. J.B. Boda, Surveyors Pvt. Ltd., located at Raghu Building, 1st Floor, Urwa Stores, Mangalore-575006 and having their registered office at Maker Bhawan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) specified in the schedule annexed hereto, prior to export at Mangalore, subject to the following conditions, namely:-

- (i) that M/s. J.B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the Officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of Export of Minerals and Ores (Group-I) (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) that M/s. J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection & Quality Control) may give in writing from time to time.

SCHEDULE

Minerals and Ores Group-I:

- (i) Iron Ore;
- (ii) Manganese Ore excluding manganese dioxide.

[File No. 5/9/97-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1997

का. आ. 1309.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसर्स आर. वी. ब्रिग्स एंड कं. प्रा. लि., 24-1-30, थोम्पसन स्ट्रीट हाऊस मंजिल, विशाखापत्तनम्-530001 को खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-1) अर्थात् कच्चे लोहे के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए 8-1-1997 से और तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :-

- (i) मैसर्स आर. वी. ब्रिग्स एंड कं. प्रा. लि., निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-1) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सके।
- (ii) मैसर्स आर. वी. ब्रिग्स एंड कं. प्रा. लि. इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा

जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देगे।

[फा. सं. 5 /15/97-ई. आई. एंड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 28th April, 1997

S.O. 1309.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, for a further period of three years from 8-1-97, M/s R. V. Briggs & Co. Pvt. Ltd., 24-1-30, Thompson Street, Haroon Manzil, Visakhapatnam-530001 as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I) namely Iron Ore, prior to export, subject to the following conditions, namely :—

- (i) that M/s. R. V. Briggs & Co. Pvt. Ltd., shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group I (Inspection) Rules, 1965,
- (ii) that M/s R.V. Briggs & Co. Pvt. Ltd., in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/15/97-EI & EP]

KUM SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1997

का. आ. 1310.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मैसर्स फैरोडो लेबोरेट्रीज जो कि 23-23-12/1 ब्रीच रोड, विशाखापत्तनम् में स्थित है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 25-6-4, गुंजम स्ट्रीट, काकोनाडा-533001 में है को खनिज तथा अयस्क के (ग्रुप-1) अर्थात् कच्चे लोहे निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए विशाखापत्तनम् में 19-2-97 से और तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :-

- (i) मैसर्स फैरोडो लेबोरेट्रीज, निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई जाने वाली निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा अयस्क (ग्रुप-1) के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जा सके।
- (ii) मैसर्स फैरोडो लेबोरेट्रीज इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा आबद्ध होगा जो निदेशक

(निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) समय-समय पर लिखित रूप में देंगे।

[फा. सं. 5/16/97-ई.आई. एंड ई. पी.]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 28th April, 1997

S.O. 1310.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises, for a further period of three years from 19-2-97, M/s. Ferrado Laboratories, located at 23-23-12/1, Beach Road, Vishakapatnam-530001 and having their registered office at 25-6-4, Ganjam Street, Kakinada-533001, as an agency for the inspection of Minerals and Ores (Group-I), namely Iron Ore prior to export at Vishakapatnam subject to the following conditions, namely :—

- (i) that M/s. Ferrado Laboratories, shall give adequate facilities to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to examine the method of inspection followed by them in granting the certificate of inspection under rule 4 of the Export of Minerals and Ores Group-I (Inspection) Rules, 1965;
- (ii) that M/s. Ferrado Laboratories in the performance of their function under this notification shall be bound by such directives as the Director (Inspection and Quality Control) may give in writing from time to time.

[File No. 5/16/97-EI & EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1997

का. आ. 1311.—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3130 तारीख 30-10-96 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, “10 कि. ग्राम और 50 कि.ग्राम” शब्दों और अंक के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“500 ग्राम और 1000 कि. ग्राम”

[फाइल सं. डब्ल्यू एम 21(28)/94]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 25th April, 1997

S.O. 1311.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution number S.O. 3130 dated 30-10-96, namely :—

In the said notification, in paragraph 3, for the words and figure “10 kg and 50 kg.”, the following words and figures shall be substituted, namely :—

“500g and 1000kg”.

[File No. WM 21(28)/94]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1997

का. आ. 1312.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड “ख” के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किए गए हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 2 : 1960	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
2.	आईएस 501 : 1976	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	आईएस 526 : 1988	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
4.	आईएस 1341 : 1992	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
5.	आईएस 1391 (भाग 1) : 1992	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
6.	आईएस 1475 : 1978	संशोधन सं. 7 जनवरी 1997	97-01-31
7.	आईएस 1571 : 1992	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
8.	आईएस 1767 : 1980	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-29
9.	आईएस 1829 (भाग 1) : 1978	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
10.	आईएस 1890 (भाग 0) : 1995	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
11.	आईएस 1890 (भाग 1) : 1995	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
12.	आईएस 1890 (भाग 2) : 1995	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
13.	आईएस 1890 (भाग 3) : 1995	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
14.	आईएस 2556 (भाग 15) : 1995	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
15.	आईएस 2796 : 1995	संशोधन सं. 1 मार्च 1997	97-03-31
16.	आईएस 3321 : 1973	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
17.	आईएस 4116 : 1988	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
18.	आईएस 4126 : 1986	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
19.	आईएस 4408 : 1979	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
20.	आईएस 4414 : 1990	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
21.	आईएस 5039 : 1983	संशोधन सं. 1 मार्च 1997	97-03-31
22.	आईएस 5447 : 1978	संशोधन सं. 3 जनवरी 1997	97-01-31
23.	आईएस 5823 : 1986	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
24.	आईएस 5923 : 1986	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
25.	आईएस 5974 : 1986	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
26.	आईएस 6903 : 1983	संशोधन सं. 3 मार्च 1997	97-03-31

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	आईएस 6188 : 1988	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
28.	आईएस 6632 : 1988	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
29.	आईएस 7070 : 1988	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
30.	आईएस 7223 : 1986	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
31.	आईएस 7259 (भाग 1) : 1988	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
32.	आईएस 8427 : 1989	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
33.	आईएस 8440 : 1977	संशोधन सं. 3 फरवरी 1997	97-02-28
34.	आईएस 8611 : 1988	संशोधन सं. 2 मार्च 1997	97-03-31
35.	आईएस 10617 (भाग 1) : 1983	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
36.	आईएस 10617 (भाग 2) : 1983	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
37.	आईएस 10617 (भाग 3) : 1983	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
38.	आईएस 10805 : 1986	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
39.	आईएस 11582 : 1985	संशोधन सं. 1 जनवरी 1997	97-01-31
40.	आईएस 11679 : 1986	संशोधन सं. 2 जनवरी 1997	97-01-31
41.	आईएस 12047 : 1987	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
42.	आईएस 12064 : 1987	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
43.	आईएस 12680 : 1989	संशोधन सं. 2 फरवरी 1997	97-02-28
44.	आईएस 13428 : 1992	संशोधन सं. 1 फरवरी 1997	97-02-28
45.	आईएस 13634 : 1993	संशोधन सं. 1 मार्च 1997	97-03-31

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कलकत्ता, चण्डीगढ़, मद्रास तथा मुम्बई और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, तथा थिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[सं. के प्र वि/13 : 5]

जी. रामन, अपर महानिदेशक

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 28th April, 1997

S. O. 1312.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) of Rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment (s) to the Indian Standard (s), particulars of which is/are given in the Schedule hereto annexed, has /have been issued :

THE SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standard (s) amended	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2:1960	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
2.	IS 501 : 1976	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
3.	IS 526 : 1988	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
4.	IS 1341 : 1992	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
5.	IS 1391 (Part 1) : 1992	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
6.	IS 1475 : 1978	Amendment No. 7 January 1997	97-01-31
7.	IS 1571 : 1992	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
8.	IS 1767 : 1980	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
9.	IS 1829 (Part 1) : 1978	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
10.	IS 1890 (Part 0) : 1995	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
11.	IS 1890 (Part 1) : 1995	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
12.	IS 1890 (Part 2) : 1995	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
13.	IS 1890 (Part 3) : 1995	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
14.	IS 2556 (Part 15) : 1995	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
15.	IS 2796 : 1995	Amendment No. 1 March 1997	97-03-31
16.	IS 3321 : 1973	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
17.	IS 4116 : 1988	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
18.	IS 4126 : 1986	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
19.	IS 4408 : 1979	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
20.	IS 4414 : 1990	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
21.	IS 5039 : 1983	Amendment No. 1 March 1997	97-01-31
22.	IS 5447 : 1978	Amendment No. 3 January 1997	97-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	IS 5823 : 1986	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
24.	IS 5923 : 1986	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
25.	IS 5974 : 1986	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
26.	IS 6003 : 1983	Amendment No. 3 March 1997	97-03-31
27.	IS 6188 : 1988	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
28.	IS 6632 : 1988	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
29.	IS 7070 : 1988	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
30.	IS 7223 : 1986	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
31.	IS 7259 (Part 1) : 1988	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
32.	IS 8427 : 1989	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
33.	IS 8440 : 1977	Amendment No. 3 February 1997	97-02-28
34.	IS 8611 : 1988	Amendment No. 2 March 1997	97-01-31
35.	IS 10617 (Part 1) : 1983	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
36.	IS 10617 (Part 2) : 1983	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
37.	IS 10617 (Part 3) : 1983	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
38.	IS 10805 : 1986	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
39.	IS 11592 : 1985	Amendment No. 1 January 1997	97-01-31
40.	IS 11679 : 1986	Amendment No. 2 January 1997	97-01-31
41.	IS 12047 : 1987	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
42.	IS 12064 : 1987	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
43.	IS 12680 : 1989	Amendment No. 2 February 1997	97-02-28
44.	IS 13428 : 1992	Amendment No. 1 February 1997	97-02-28
45.	IS 13631 : 1993	Amendment No. 1 March 1997	97-03-31

Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras, and Mumbai and also Branch Offices: Ahmadabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Patna, and Thiruvananthapuram.

[No. CMD/13:5]

G. RAMAN, Addl. Director General.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम और खेल विभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1313.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसरण में भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्नलिखित 3 कार्यालयों को जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	क्षेत्र
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण, : नेताजी सुभाष केन्द्रीय केन्द्र, आई.जी. स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002.	भारत की राजधानी	“क”
2.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष उत्तरी केन्द्र, हॉकी स्टेडियम, सेक्टर-42 चण्डीगढ़	केन्द्र शासित क्षेत्र	“क”
3.	भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष पश्चिमी केन्द्र, सेक्टर-15, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गांधी नगर (गुजरात)-382 015.	गुजरात	“ख”

[मि. संख्या ई. 11011/5/97-हि.ए.]

आशा स्वरूप, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Youth Affairs and Sports)

New Delhi, the 29th April, 1997.

S.O. 1313.—In pursuance of rule 10 (4) of the Official Language (use of official purposes of the Union) Rule 1976, the Central Government hereby notifies the following 3 offices of Sports Authority of India the staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

S.No.	Name of the Office	State/UT	Region
1.	Sports Authority of India, Netaji Subhash Central Centre, I.G. Stadium, I.P. Estate, New Delhi - 110002.	Capital of India	“A”
2.	Sports Authority of India, Netaji Subhash Northern Centre, Hockey Stadium, Sector - 42, Chandigarh	UT	“A”
3.	Sports Authority of India, Netaji Subhash Western Centre, Sector - 15, Sports Complex, Gandhinagar 382015	Gujarat	“B”

[F.No. E-11011/5/97-H.U.]

ASHA SWAROOP, Jt Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का.आ. 1314.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), के उपबंधों के अनुसरण में, डा. यू. सी. सामल, एम.डी. सह-आचार्य, प्रमुख हृदय रोग प्रभाग, आयुर्विज्ञान विभाग, पटना मेडिकल कालेज, पटना को पटना विश्वविद्यालय की सिनेट द्वारा 18 जनवरी, 1997 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “धारा 3 की उपधारा (क) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” के अधीन, क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“17. डा. यू. सी. सामल, एम. डी. पटना विश्वविद्यालय”
सह-आचार्य प्रमुख हृदय रोग प्रभाग,
आयुर्विज्ञान विभाग, पटना मेडिकल
कालेज, पटना।

[सं. बी. 11013/1/97 एम.ई.(यू.जी.)]

एस. के. मिश्र, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में का. आ. संख्या 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**Ministry of Health and Family Welfare
(Department of Health)**

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1314.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. U. C. Samal, M.D. Associate Professor, Chief of Cardiology Division, Department of Medicine, Patna Medical College, Patna has been elected by the Senate of the Patna University to be a member of Medical Council of India from 18th January, 1997,

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading, “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, for serial number 17 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“17. Dr. U. C. Samal, M. D. Patna University”
Associate Professor,
Chief of Cardiology Division,
Department of Medicine,
Patna Medical College,
Patna

[No.V 11013/1/97-ME(UG)]

S. K. MISHRA, Desk Officer

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No. 138, dated 9-1-1960.

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का.आ. 1315.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख), के उपबंधों के अनुसरण में, डा. एस. के. पाठक, आचार्य और विभागाध्यक्ष न्याय आयुर्विज्ञान, एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर को 10 दिसम्बर, 1996 से राजस्थान विश्वविद्यालय की सिनेट द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 138, तारीख 9 जनवरी, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, शीर्षक “धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित” के अधीन, क्रम सं. 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“19. डा. एस. के. पाठक, राजस्थान विश्वविद्यालय”
आचार्य और विभागाध्यक्ष न्याय
आयुर्विज्ञान, एस. एम. एस. मेडिकल
कालेज, जयपुर।

[सं. बी. 11013/23/96 एम.ई.(यू.जी.)]

एस. के. मिश्र, डेस्क अधिकारी

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में का. आ. संख्या 138, दिनांक 9 जनवरी, 1960 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1315.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. S.K. Pathak, Professor, and Head of the Department of Forensic Medicine, S.M.S. Medical College, Jaipur has been elected by the Senate of the Rajasthan University to be a member of Medical Council of India from 10th December, 1996;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health number S.O. 138, dated the 9th January, 1960, namely:—

In the said notification, under the heading, “Elected under clause (b) of sub-section (1) of section 3”, for serial number 19 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“19. Dr. S.K. Pathak, Rajasthan University”
Professor, and Head of
Department of Forensic Medicine,
S.M.S. Medical College,
Jaipur.

[No.V. 11013/23/96-ME(UG)]

S.K. MISHRA, Desk Officer

Foot Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, vide S.O. No. 138, dated 9-1-1960.

खाद्य मंत्रालय
(खाद्य प्रापण और वितरण विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का. आ. 1316.—अतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य मंत्रालय, क्षेत्रीय खाद्य निदेशक उपापत्ति निदेशालय और खाद्य मंत्रालय के सेवन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारण, संचालन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बंद कर दिया था जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य थे।

और अतः खाद्य मंत्रालय क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों में कार्य कर रहे और उपरिखणित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा केन्द्रीय सरकार के दिनांक 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें उल्लिखित निर्धारित तिथि के अन्दर यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी थी।

और जबकि निम्नलिखित कर्मचारी की सेवाएं अभी तक भारतीय खाद्य निगम को अंतरित नहीं की गई हैं।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारी को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की तारीख
1.	श्री किशोर चन्द शर्मा	तोल/गोदाम लिपिक	तोल/गोदाम लिपिक	3-1-1997

[सं. ए-38022/2/95-एफ. सी. 3]

सत्य नारायण गुप्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD
(Department of Food Procurement & Distribution)
ORDER

New Delhi, the 24th April, 1997

S.O. 1316.—Whereas the Central Govt. had ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transportation, distribution and sale of foodgrains done by the Ministry of Food, Regional Director of Food, the procurement Directorates and the Pay & Accounts Office of the Ministry of Food which under Section 13 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) were the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following employee serving in the Regional Directorate of Food, and engaged in the performance of the functions mentioned above had not, in response to the circular of the Central Govt. dated the 16th April, 1971

1096GI/97—8

intimated within the date specified therein his intension of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (I) of Section 12A of the said Act.

And whereas the Services of the following employee have not yet been transferred to Food Corporation of India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964), as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following employee to the Food Corporation of India with effect from the date indicated against his name.

S. No.	Name of the Officer/Employee	Permanent Post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the Food Corp. of India
1.	Shri Kishore Chand Sharma	Weighment/Godown Clerk	Weighment/Godown Clerk	3-1-1997

[No. A-38022/2/95-FC. 3]

S. N. GUPTA, Under Secy.

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय
(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1997

का. आ. 1317.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (छ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्री के. के. भटनागर तथा श्री एम. एस. श्रीनिवासन और श्री एम. एस. श्रीनिवासन के विकल्प के रूप में श्री आर. के. सिंह के बदले में श्री बी. सुरेश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको तथा श्री बी. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव और श्री बी. एस. मिन्हास के विकल्प के रूप में डा. निवेदिता पी. हरन, निदेशक को दिल्ली विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की दिनांक 30-12-1997 की अधिसूचना सं. 12-173/57-एल. एस. जी. में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा :—

1. मद सं. 9 में "श्री एम. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव और श्रीनिवासन के विकल्प स्वरूप श्री आर. के. सिंह, निदेशक" नामक प्रविष्टि के स्थान पर "श्री बी. एस. मिन्हास, संयुक्त सचिव और श्री मिन्हास के विकल्प स्वरूप डा. निवेदिता पी. हरन, निदेशक" प्रविष्टियां रखी जाये।
2. मद सं. 10 में "श्री के. के. भटनागर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको नामक प्रतिष्ठि के लिए श्री बी. सुरेश,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको" नामक प्रविष्टि रखी जाये।

[सं. के-11011/20/97-डी डी 1 ए]

बी. के. मिश्रा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT
(Department of Urban Development)
(Delhi Division)

New Delhi, the 29th April, 1997

S.O. 1317.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (g) of sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957); the Central Government hereby nominates Shri V. Suresh, Chairman & Managing Director, HUDCO and Shri B. S. Minhas, Joint Secretary with Dr. Nivedita P. Haran, Director as alternate to Shri Minhas, as Members of Delhi Development Authority vice Shri K. K. Bhatnagar and Shri M. S. Srinivasan with Shri R. K. Singh as alternate to Shri Srinivasan respectively and makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Health No. 12-173/57-LSG dated 30-12-1957, namely :—

- (i) In item No. 9, for the entry "Shri M. S. Srinivasan, Joint Secretary with Shri R. K. Singh, Director as alternate to Shri M. S. Srinivasan", the following entry shall be substituted, namely, "Shri B. S. Minhas, Joint Secretary with Dr. Nivedita P. Haran, Director as alternate to Shri B. S. Minhas."
- (ii) In item No. 10, for the entry "Shri K. K. Bhatnagar, Chairman & Managing Director, HUDCO, the following entry shall be substituted, namely, "Shri V. Suresh, Chairman & Managing Director, HUDCO."

[No. K-11011/20/97-DDIA]

V. K. MISRA, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1997

का. आ. 1318.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 17-4-1997 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/880/87 डी-2(ए)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st April, 1997

S.O. 1318.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and their workman, which was received by the Central Government on the 17-4-97.

[No. L-12012/880/87 D-2-(A)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 41/1988

रिफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक 12012/880/87-डी-2(ए) दिनांक 13-7-88

ऑल राजस्थान स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एम्प्लॉईज एसोसिएशन, परवाना भवन, जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री आर.सी. शर्मा, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी संघ की ओर से

श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से

श्री मनीष भण्डारी

दिनांक अवाई

13-1-1997

अवाई

केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित विवाद इस अधिकरण को संप्रेषित किये जाने पर दिनांक 18-7-88 को यह प्राप्त हुआ :

"क्या स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबन्धन के सर्वश्री एन.सी. सिंघवी, गौतम अंबलिया और डी. के. बिस्सा को परीक्षा अवधि को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से शुरू करने से इंकार करने और उनकी खरिफ्टता को अस्थाई आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से गणना न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

2. प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत वाद विवरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि सर्वश्री एम. सी. सिंघवी, गौतम अंबलिया व डी. के. बिस्सा विपक्षी संस्थान में कार्यरत हैं जिनकी नियुक्ति से संबंधित तथ्य प्रार्थी संघ द्वारा पृथक पृथक दर्शाये गये हैं। श्री एम.सी. सिंघवी को विपक्षी बैंक ने दिनांक 2-12-67 से 10-12-71 तक स्थाई रिक्ति के आधार पर नियुक्त किया

था, जिसे विपक्षी बैंक ने दर्शाई गई विवरणों के अनुसार कृत्रिम ब्रेक दिया। उसे दिनांक 11-12-71 को छः माह की परीक्षा के आधार पर जोधपुर में विपक्षी बैंक की शाखा में नियुक्त किया गया। विपक्षी ने दिनांक 11-12-71 से उसे परीक्षा के आधार पर रखा तथा वह दिनांक 2-12-67 से दिनांक 30-11-70 तक लिपिक व गोदाम पाल के रूप में कार्य करता रहा। कर्मकार की सेवा में दिये गये कृत्रिम ब्रेक गैर कानूनी हैं क्योंकि बैंक ने उसे स्थाई नहीं होने देने के लिए ये ब्रेक दिये थे। उसे दिनांक 1-4-70 से परीक्षा पर माना जाना चाहिये था क्योंकि वह दिनांक 1-4-70 से निरन्तर नौकरी पर है। दिनांक 1-4-70 से उसकी परीक्षा मानकर उसका स्थाईकरण दिनांक 1-10-70 से होना चाहिये था जो बैंक ने नहीं किया।

3. श्री गौतम आंचलिया के संबंध में यह लेख किया गया है कि उसे विपक्षी बैंक ने दिनांक 14-9-72 को जोधपुर शहर शाखा में पदस्थापित किया जिससे दिनांक 2-12-71 तक कार्य लिया। इसके पश्चात् दिनांक 6-12-72 को उसे परीक्षा के रूप में रखा गया व उसकी सेवा में दिनांक 3-12-72 से दिनांक 5-12-72 तक तीन दिन का कृत्रिम ब्रेक दिया गया। उसे दिनांक 14-9-72 से परीक्षा पर माना जाना चाहिये था जबकि उसे दिनांक 6-12-72 से माना गया है। ये ब्रेक कृत्रिम हैं।

4. श्री डी.के. बिस्सा को विपक्षी बैंक ने दिनांक 1-8-66 से दिनांक 5-12-69 तक विपक्षी बैंक की औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर शाखा में कार्य पर रखा। उसकी सेवा संबंधी सारणी के अनुसार उसकी सेवा में 6 ब्रेक दिये गये। प्रार्थी संघ के अनुसार उसकी सेवा दिनांक 1-8-66 से दिनांक 22-12-69 तक की सम्मिलित करते हुए निरन्तर मानी जाये तथा उसे दिनांक 1-8-66 से परीक्षा पर माना जावे।

5. इस प्रकार प्रार्थी संघ ने यह अधिकथन किया है कि इन तीनों कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता अवधि को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि को शुरू करने से माना जाये व उनका वरिष्ठता क्रम उसी अनुरूप दिया जावे।

6. उत्तर वाद विवरण के अन्तर्गत विपक्षी ने यह लेख किया है कि तीनों कर्मकार प्रार्थी संघ द्वारा दर्शाई गई दिनांकों से स्थाई माने जाने के हकदार नहीं हैं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम मियाद बाहर है। यह 18 वर्ष की देरी से प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण वे कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। बैंक में स्थाई सेवा नियुक्ति की एक प्रक्रिया है जिसे अपनाने के पश्चात् ही स्थाई नियुक्ति दी जाती है। अस्थाई नियुक्ति इस प्रक्रिया को अपनाये बिना बैंक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित अवधि के लिए दी जाती है जो कर्मकार के स्वीकार करने पर की जाती है और वे इस प्रकार की अवधि का क्लेम उठाने के हकदार नहीं हैं। विपक्षी बैंक के अनुसार यह क्लेम अत्यधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है व इससे अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बैंक की किसी शाखा में अचानक अधिक कार्य बढ़ जाने से अथवा कर्मचारियों के अधिक अनुपस्थित हो जाने पर वे शाखाएं अस्थाई तौर पर कर्मचारियों को नियुक्त कर लेती हैं तो अस्थाई कर्मचारी कहलाते हैं। इन्हें एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति दी जाती है तथा अस्थाई कर्मचारी बिना किसी परीक्षा को पास किये स्थाई नियुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। स्थाई चयन की प्रक्रिया पृथक है जिस हेतु कर्मकार का चयन होने पर नियमानुसार उसे 6 माह हेतु परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा उसका कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर उसे स्थाई नियुक्ति दी जाती है।

7. तीनों कर्मचारियों से संबंधित प्रकरण पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी बैंक द्वारा श्री एम.सी. सिंघवी के संबंध में यह लेख किया गया है कि उसे स्थाई रिक्तता के विरुद्ध नियुक्ति नहीं दी गई थी अपितु उसकी नियुक्ति हीराकरसिंग प्रा.लि. बोरोवर, के खर्चे पर निवासीय गोदाम कीपर के पद पर की गई थी जिसकी अवधि के समाप्त हो जाने पर उसकी सेवा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। स्थाई प्रक्रिया के अनुसार इसके पश्चात् श्री सिंघवी की नियुक्ति को जाकर उसे 6 माह के परीक्षा काल पर रखा गया था। उसे दिनांक 1-4-70 से परीक्षा पर नहीं माना जा सकता तथा उसके द्वारा यह विवाद 18 वर्ष बाद उठाया गया है। श्री गौतम आंचलिया के संबंध में यह लेख किया गया है कि स्थाई प्रक्रिया के अनुसार उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा किये गये कार्य को स्थाई नियुक्ति के दिवसों में नहीं जोड़ा जा सकता तथा उसके द्वारा विवाद 16 वर्ष बाद उठाया गया है। यह अभिवचन श्री बिस्सा के संबंध में विपक्षी द्वारा अपनाया जाकर उसके द्वारा विवाद 19 वर्ष पश्चात् उठाया जाना लेख किया गया है।

8. प्रत्युत्तर के अन्तर्गत प्रार्थी संघ द्वारा यह लेख किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत कोई मियाद निर्धारित नहीं है तथा इन कर्मकारों की मांग के संबंध में प्रार्थी संघ विपक्षी बैंक को लगातार लिखित व मौखिक निवेदन करता रहा व विपक्षी बैंक को यह अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है।

9. साक्ष्य के अन्तर्गत प्रार्थी संघ की ओर से सर्वश्री गौतम आंचलिया, एम.सी. सिंघवी व डी. के. बिस्सा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे क्रमशः प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया। विपक्षी बैंक की ओर से श्री सी.एस. पालीवाल, मुख्य प्रबन्धक का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिससे प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा प्रति परीक्षण किया गया।

10. दोनों पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

11. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा संकथन किया गया कि श्री एम.सी. सिंघवी ने दिनांक 2-12-67 से कार्य प्रारंभ किया जिसकी सेवा में विपक्षी बैंक ने दो कृत्रिम ब्रेक दिये। इसी भांति गौतम आंचलिया की सेवा में एक व श्री डी. के. बिस्सा की सेवा में छः कृत्रिम ब्रेक विपक्षी बैंक ने दिये। उनका तर्क है कि ये ब्रेक कम समय के हैं जो कृत्रिम हैं और केवल इसलिए विपक्षी बैंक ने दिये हैं ताकि उनको सेवा में निरन्तर नहीं माना जा सके। इनके द्वारा वर्ष में 240 दिन काम किया गया है इसलिए इनकी सेवा निरन्तर मानी जाए तथा इनकी प्रारंभिक नियुक्ति को दिनांक से इनको वरिष्ठता दी जाए। इन तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी के तर्क हैं कि इन तीनों कर्मकारों को प्रारंभिक नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी जिसके लिए उनका चयन नहीं किया गया था। चयन के पश्चात् उनकी नियमानुसार नियुक्ति की गई और उन्हें छः माह के प्रोबेशन पर रखा गया तथा उस दिनांक से उनकी वरिष्ठता मानी गई है। उनकी चयन के अनुसार जो नियुक्ति की गई उसके अनुसार उनका पद भी उनके पूर्व पद से पृथक था। विद्वान प्रतिनिधि का यह भी तर्क है कि कर्मकारों को सेवा में जो ब्रेक दिये गये हैं उस संबंध में कोई रैफरेंस नहीं है अतः यह अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा वरिष्ठता कर्मकार की नियमित नियुक्ति को दिनांक से मानी जाती है। उन्होंने इस तथ्य को भी चुनौती दी है और तर्क किया है कि विपक्षी बैंक द्वारा कृत्रिम ब्रेक कर्मकारों की सेवा में नहीं दिये गये हैं।

12. मैंने उक्त तर्क वितर्कों पर विचार एवं मनन किया तथा प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सावधानीपूर्वक परिशोधन किया।

13. सर्वप्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विपक्षी बैंक द्वारा कर्मकारों की सेवा में कृत्रिम व्यवधान दिया गया अथवा क्या कर्मकारों की सेवा में उत्पन्न हुए क्रम भंग विपक्षी बैंक द्वारा आशयपूर्ण किये गये थे। प्रार्थी संघ द्वारा श्री एम.सी. सिंघवी की सेवा में क्रमशः तीन-तीन दिवस के दो व्यवधान, श्री डी. के. बिस्सा की सेवा में क्रमशः चार दिवस, 5 दिवस, 3 दिवस, 3 दिवस, 5 दिवस व 17 दिवस के छः व्यवधान एवं श्री गौतम आंचलिया की सेवा में दिनांक 3-12-72 से 5-12-72, तीन दिवस का एक व्यवधान होना दर्शाया गया है, इन्हें विपक्षी बैंक द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी का यह तर्क है कि इस विवाद के अन्तर्गत निर्णायक बिन्दु यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मकारों की सेवा में उत्पन्न हुए व्यवधान के संबंध में अभिनिर्देशन नहीं किया गया है। अतः इस बिन्दु पर विचार किया जाना इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे है। किन्तु विद्वान प्रतिनिधि विपक्ष का यह तर्क सारवान होना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि संदर्भित विवाद के अन्तर्गत अवधारणीय बिन्दु यह है कि क्या कर्मकारों को प्रारंभिक नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता सुनिश्चित की जा सकती है अथवा नहीं? वरिष्ठता सुनिश्चित किये जाने का केन्द्र बिन्दु कर्मकारों की सेवा में उत्पन्न हुए क्रम भंग ही हैं। अतः क्रम भंग का महत्वपूर्ण बिन्दु इस विवाद में अन्तर्बिलित है जिसके कारण यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि संदर्भित अभिनिर्देशन में केवल मात्र व्यवधान की अभिव्यक्ति के अभाव में यह विवाद अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे हो जाता है अथवा यह अभिनिर्देशन दोषपूर्ण हो जाता है। अतः विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क अमान्य है।

14. विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ का तर्क है कि इन तीनों कर्मकारों की सेवा में जो व्यवधान उत्पन्न हुए हैं वे विपक्षी बैंक द्वारा कृत्रिम रूप से किये गये हैं। अतः उनकी प्रारंभिक नियुक्ति को दिनांक से ही उनकी वरिष्ठता मानी जाये तथा तभी से उनकी सेवा की निरन्तरता भी मानी जाये। इसका प्रतिवाद विद्वान प्रतिनिधि विपक्षी द्वारा किया गया है तथा यह दर्शाया गया है कि बैंक की आवश्यकता के अनुसार अस्थायी रूप से इन कर्मकारों की प्रारंभ में नियुक्ति की गई थी जो कि बैंक के नियमों के अन्तर्गत चयन के आधार पर नहीं थी तथा जब से इन नियमों के अन्तर्गत इन कर्मकारों का चयन किया जाकर उनकी नियुक्ति की गई उस नियुक्ति की दिनांक से परिबीक्षा काल की अवधि समाप्त होने पर उनकी वरिष्ठता मानी गई है।

15. विपक्षी बैंक द्वारा प्रचलित नियुक्ति पत्र दिनांक 3-12-71 के अनुसार श्री सिंघवी की नियुक्ति लिपिक के पद पर 6 माह की परिबीक्षा के आधार पर की गई। श्री सिंघवी ने अपने शपथ पत्र में यह नियुक्ति 11-12-71 से किया जाना प्रकट किया है। विपक्षी बैंक के अपने आदेश में दिनांक 28-11-72 के अनुसार श्री आंचलिया की नियुक्ति लिपिक व गोदामकीपर के पद पर 6 माह की परिबीक्षा के आधार पर की। श्री आंचलिया ने अपने शपथ पत्र में यह नियुक्ति 6-12-72 से की जाना स्वीकार किया है। इसी भांति श्री डी. के. बिस्सा की नियुक्ति विपक्षी बैंक द्वारा आदेश दिनांकित 1-12-69 के द्वारा खजान्ची व गोदाम कीपर के पद पर 6 माह की परिबीक्षा के आधार पर की जो श्री बिस्सा ने अपने शपथ पत्र में 1-12-69 से ही की जाना स्वीकार किया है। यह तीनों नियुक्तियां विपक्षी बैंक द्वारा इन कर्मकारों के चयन के आधार पर स्थाई रिक्तता के विरुद्ध किया जाना प्रकट किया गया है। प्रार्थी संघ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हुआ

है अथवा वह इस बिन्दु पर ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि इन कर्मकारों की प्रारंभिक नियुक्ति विपक्षी बैंक द्वारा चयन के आधार पर की गई थी। श्री सिंघवी के संबंध में विपक्षी बैंक द्वारा यह स्पष्ट लेख किया गया है कि उसकी नियुक्ति हीराकरसिंह प्राईवेट लि. बारोवर के खर्च पर निवासीय गोदाम कीपर के पद पर की गई थी जिसकी समाप्ति उस अवधि के समाप्त होते ही हो जाती है। इसी भांति अन्य दोनों कर्मकारों की नियुक्ति भी अस्थायी तौर पर पृथक पद पर की गई थी तथा चयन के पश्चात् उनकी नियुक्ति एक पृथक पद पर हुई है। इन तथ्यों के आधार पर यह प्रकट होता है कि इन कर्मकारों की प्रारंभिक नियुक्ति से व चयन के आधार पर की गई नियुक्ति से पूर्व की अवधि में जो उनको सेवा में क्रम भंग उत्पन्न हुए हैं, वे विपक्षी बैंक द्वारा आशयपूर्ण नहीं किये गये हैं अपितु ये व्यवधान परिस्थितिजन्य हैं जिनके लिए विपक्षी बैंक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इस संबंध में प्रार्थी संघ की ओर से यह नहीं दर्शाया जा सका है कि कर्मकारों को प्रारंभिक नियुक्ति चयन के आधार पर हुई थी। विपक्षी बैंक द्वारा इन कर्मकारों की वरिष्ठता उनकी चयन के आधार पर की गई नियुक्ति की दिनांक से निश्चित की गई है जो उनकी परिबीक्षा अवधि के समाप्त होने के पश्चात् मानी गई है। किसी कर्मकार की वरिष्ठता उसके नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई नियुक्ति की दिनांक से ही मानी जाती है तथा ऐसा करते समय विपक्षी बैंक द्वारा कोई विविध विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है। विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं :—

1987 (TT) एल. एल. एन. (मान. गुजरात उच्च न्या.)

684 के अन्तर्गत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मकार की सेवा में कृत्रिम व्यवधान अवैध, अनुचित अन्यायपूर्ण व उत्पीड़क हैं तथा राज्य का यह आचरण के कर्मकार को माह में 28 या 29 दिन कार्य पर रखना, विधि की अनुज्ञा के बिना व अनुचित आचरण है। किन्तु विचाराधीन प्रकरण के अन्तर्गत ऐसा कोई आचरण विपक्षी बैंक द्वारा नहीं अपनाया गया है। इसी भांति 1983 लैब. आई. सी. (एन.ओ.सी.) पंजाब व हरियाणा 134 विनिश्चय के तथ्य इस प्रकार हैं कि कर्मकार 6 वर्ष तक दैनिक वेतन भोगी पद पर कार्यरत रहा व उसकी सेवा में केवल एक दिन का व्यवधान उत्पन्न हुआ। उसके द्वारा 240 दिवस कार्य किये जाने के आधार पर उसकी सेवा निरन्तर होनी माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा माना गया। विचारणीय प्रकरण में कर्मकारों की सेवा में 2, 6 व 1 व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, श्री आंचलिया की सेवा में तीन दिवस का व्यवधान उत्पन्न हुआ है जिसे कृत्रिम होना भी नहीं माना गया है। अतः संदर्भित न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य विचारणीय प्रकरण के तथ्यों के एक रूप नहीं होने के कारण इनसे प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि के तर्क का मण्डन नहीं हो पाया है।

15. इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण विचार बिन्दु इस प्रकरण में यह भी अन्तर्बिलित है कि प्रार्थी संघ द्वारा उठाया गया यह विवाद अत्याधिक विलम्बपूर्ण है जिसका याचित अनुतोष पर क्या प्रभाव पड़ता है।

16. प्रार्थी संघ द्वारा अपनाये गये अधिवचन के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है अतः इसके आधार पर अनुतोष प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होता है। इस संबंध में विद्वान प्रतिनिधि प्रार्थी संघ द्वारा 1996 (2) एल.एल.एन. (कलकत्ता) 611 विनिश्चय को प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत यह प्रस्तावित किया गया है कि अंतरिम राहत सेवा मुक्ति की दिनांक से स्वीकार की जा सकती है चाहे सेवा मुक्ति के 12 वर्ष बाद सर्वप्रथम औद्योगिक विवाद उठाया गया हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम में विवाद उठाने की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई अतः औद्योगिक विवाद उठाने में विलम्ब का कोई महत्व नहीं है।

17. उक्त विनिर्णय के विरुद्ध 1996 लेब. आई. सी. (पंजाब व हरियाणा) 45 तथा 1994 एफ. एल. आर. (पंजाब व हरियाणा) 1006 दृष्टांतों के अन्तर्गत क्रमशः 5 वर्ष व 10 वर्ष का विलम्ब विवाद में उठाने में होने के कारण अनुतोष को अस्वीकार किया गया है। इसी भांति 1959 (TT) एल.एल.जे. (मान. सर्वोच्च न्या.) 26 दृष्टांत के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि अभिनिर्देशन फाईल करने हेतु कोई परिसीमा निश्चित नहीं है किन्तु उसे उचित समय के अन्तर्गत संप्रेषित किया जाना चाहिये। इस प्रकरण के अन्तर्गत श्रमिक द्वारा 5 वर्षों तक अपना विवाद संबंधित अधिकारी के समक्ष नहीं उठाये जाने पर उसको अनुतोष अस्वीकार किया गया है।

18. अपने प्रति-परीक्षण में श्री गौतम आंचलिया ने यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 20-4-74 को संबंधित आपत्ति उठाई थी। श्री सिंघवी ने भी प्रति-परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि खरिष्टता का विवाद उसने अप्रैल, 1973 में उठाया था। श्री बिस्सा ने अपनी साक्ष्य में यह आपत्ति 1971 में उठाई जाना प्रकट किया है। इस प्रकार कर्मकारों ने उनकी साक्ष्य में उत्पन्न हुए तथ्यों के आधार पर श्री आंचलिया ने लगभग 14 वर्ष पश्चात, श्री सिंघवी ने 15 वर्ष पश्चात व श्री बिस्सा ने 17 वर्ष पश्चात यह विवाद उठाया है जो कि अत्याधिक विलम्बपूर्ण है तथा जिसका कोई खित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः संदर्भित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी संघ विलम्ब के बिन्दु के आधार पर ही याचित अनुतोष प्राप्त करने का पात्र नहीं है। 1959 (TT) एल.एल.जे. (मान. सर्वोच्च न्या.) 26 विनिश्चय के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर समरूप होने के कारण यह दृष्टांत इस प्रकरण पर प्रभावी होते हैं जो कि इस अधिकरण के लिए बाध्यकारी हैं। अतः प्रार्थी संघ द्वारा यह विवाद अत्यन्त विलम्बपूर्ण उठाया गया है जिसके कारण प्रार्थी संघ की अभ्यर्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

19. उक्त विवेचन के आधार पर यह विवाद इस प्रकार उत्तरित किया जाता है कि विपक्षी बैंक के प्रबन्धतंत्र की कर्मकारों सर्वश्री एम.सी. सिंघवी, गौतम आंचलिया व डी.के. बिस्सा की परिवीक्षा अवधि को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की दिनांक से ही प्रारूप नहीं करने व उनकी खरिष्टता की अस्थाई आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति की दिनांक से गणना नहीं करने की कार्यवाही न्यायोचित एवं सही है तथा कर्मकार याचित अनुतोष प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

20. प्रकरण में उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

आर. सी. शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1997

का.आ. 1319.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी. सी. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं.-1), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल.-20012/315/89-आई आर (सी-आई)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd April, 1997

S.O. 1319.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 1) Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/S. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 21-4-97

[No. L-20012/315/89-IR(C-I)]

K.V.B. Unny, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)(2A)
of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 65 of 1990

Parties : Employers in relation to the management of
Putki Balihari Area of M/S. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

Present : Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer.

Appearances :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri J.P. Singh, Advocate.

State : Bihar.

Industry : Coal.

Dated, the 4th April, 1997

AWARD

By Order No. L-20012/315/89-I.R. (Coal-I) dated 'nil' the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of Shri Manoj Kumar Sinha, Typist cum-Clerk, Putki Balihari Area of M/S. Bharat

Coking Coal Limited, for reinstatement in service with full back wages is justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

2. The workman has appeared and filed written statement individually and not through sponsoring union and has stated that he was Typist-cum-Clerk, Putki Balihari Area and had raised dispute individually before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Dhanbad and after failure of the same the dispute was referred by the Ministry. It is said that while he was working as typist-cum-clerk a chargesheet dated 14/15-3-83 alleging his involvement in fake appointment of Surya Bhushan Prasad and others and he was put under suspension. He submitted his reply refuting the charges levelled against him and after having received the reply the management did not hold enquiry and continued the order of suspension for about four years and criminal case was lodged against him and on his representation the domestic enquiry was held in haste without waiting decision of the competent court of law. It is said that an F.I.R. was lodged by the management which was registered as R.C. Case No. 5/83(D) T.R. No. 1/86 in which also Special Magistrate did not hold him guilty and acquitted him from all charges. He also said that the management ought not to have instituted with departmental enquiry during the pendency of the criminal case and this judgement of acquittal was completed on 29-8-86 and the management dismissed the workman from service illegally and arbitrarily and this order of dismissal was without jurisdiction. It is further said that Shri B.M. Lal was appointed as Presenting Officer who was personally biased against him as he had filed an FIR against Sri B.M. Lal earlier and it is also said that during the period the workman was office bearer of Colliery Karmachari Sangh affiliated to Bhartiya Mazdoor Sangh and organised by demonstrations for fulfilment of the demand of the workmen in course of which some altercation took place with Sri B.M. Lal against whom an FIR was lodged by the concerned workman on 10-6-85 and for the same reason Sri S.N.P. Sinha Enquiry Officer, was also biased against him as he was a member of the same Officers' Association. He also said that no proper opportunity was given to him to defend his case and finding of the departmental enquiry was perverse. It is also said that there was no evidence at all to substantiate the charges against the workman and it is finally stated that the dismissal order be revoked and he reinstated in service.

3. I further find that the management has appeared and filed written statement stating, inter-alia, that the reference was not legally maintainable and it is said that from December, 1981 to October, 1982 several workmen were inducted into the employment of Bhagaband Area No. VII presently known as Putki-Balihari Project by fabricating appointment letters issued under forged signature of Sri R.P. Singh, the then Dy. Personnel Manager (MP) incharge of recruitment of workmen at Headquarter and posting them at different areas. It is said that the concerned workman was one of the persons involved in fabricating of appointment letters with forged signature of Sri R.P. Singh and he actively aided and abetted

the workmen in procuring the appointments and being posted at different jobs in area No. VII. It is said that he committed serious misconduct of theft, fraud and dishonesty in connection with employer's business. It is said that a chargesheet was issued to the workman under signature of the General Manager/Chief Mining Engineer for the charges and the workman submitted his reply dated 25-3-83 denying the allegations levelled against him in the chargesheet and Sri S. N. P. Sinha, the then Personnel Manager was appointed as Enquiry Officer and Sri B.M. Prasad, Dy. Personnel Manager was appointed as Presenting Officer by the General Manager/Chief Mining Engineer of Bhagaband Area No. VII. The departmental enquiry was held on 15-7-83 onwards and after its completion on 7.8.87 and this longer period of enquiry was due to delaying tactics adopted by the chargesheeted workman concerned in the joint enquiry. It is said that the departmental enquiry was held in presence of the chargesheeted workman and full opportunity was given to them to cross-examine the management's witnesses and to give their own statements and to produce defence witnesses and the chargesheeted workmen availed full opportunity to defend themselves and they did not make any complaint against the Enquiry Officer of against the manner of conducting departmental enquiry. The Enquiry Officer submitted his report dated 30-8-88 holding the concerned workman guilty of the misconducts charged against him, and thereafter the concerned workman was dismissed from service by letter dated 25-6-88 under the signature of General Manager/Chief Mining Engineer.

4. By way of rejoinder to the written statement of the workman the contentions of the workman have been denied specifically and parawise and the same was said to be not correct and denied. It is also denied that the Enquiry Officer, Sri S.N.P. Sinha was biased against the concerned workman and it is also submitted that Sri S.N.P. Sinha had no connection with Sri B.M. Lal and it is said that Sri B.M. Lal was appointed Presenting Officer in the year 1983 and the enquiry was proceeding since then. It is said that Sri B.M. Lal was designed to intimidate the presenting officer not to present witnesses and not to produce documents before the Enquiry Officer. It is also said that misconduct of the workman was highly serious regarding fraud and dishonesty and played pressure tactics against Sri B.M. Lal and to intimidate him from acting as Presenting Officer. Other allegations are also said to be incorrect and it is denied. It is absolutely said that the workman was rightly dismissed from service due to his serious misconduct and finding him guilty in the departmental enquiry in his presence.

5. I further find that a rejoinder has also been filed by the workman to the written statement of the management and contentions of the written statement filed by the management have been denied specifically and parawise and the same is said to be incorrect and mala fide and denied. It is also said that the Enquiry Officer submitted perverse report on the basis of no evidence at all. It is finally said that an award be passed accordingly.

6. On the basis of pleadings of the parties following points are to be decided in this reference :

- (a) Whether the demand of the concerned workman, Manoj Kumar Sinha for reinstatement in service with full back wages is justified or nor?
- (b) If so, what relief or reliefs the concerned workman is entitled?

7. Both the points are interlinked and as such are taken together for their consideration.

8. It is to be noted here that fairness and propriety of the domestic enquiry was taken as preliminary issue on the request of parties and for that the management has examined MW-1—S N P. Sinha, Enquiry Officer, who since has retired as General Manager (Administration) from 1-3-1992. He conducted domestic enquiry in respect of six workmen for commission of misconduct and the chargesheets issued against them are Exts. M-1 to M-1/5 and reply given by them are Exts. M-2 to M-2/5 and two letters issued by the General Manager of Bhagaband Area about conducting enquiry, marked Ext. M-3 and M-3/1. Notice of enquiry given to all the workmen is Ext. M-4. The letter issued by the Chief Personnel Manager is Ext. M-5 and another letters issued by the Acting General Manager are Exts. M-6 and M-7. Three other letters issued by the Dy. Personnel Manager have been marked Ext. M-8 to M-10 and the application given by all the workmen in the enquiry is Ext. M-11 and some other letters produced during the enquiry kept in register was marked Ext. M-12. Series and file contain entire domestic enquiry proceeding. He recorded the statements of the witnesses in his own hand and gave full opportunity to cross-examine the witnesses and to give their own witnesses and their own statement. He read over statements given by the witnesses to the workmen and being satisfied they have put their signature and also mentioned that it was recorded correctly. Documents produced during the enquiry were Ext. M-12. He submitted enquiry report Ext. M-13 and he found all the six workmen including the present workman guilty of the charges levelled against them. He has also proved notesheet of Dy. Chief Personnel Officer and approval of General Manager, marked Ext. M-14 and M-14/1 and dismissal orders to the workmen marked Ext. M-15 and M-15/1. He has further stated that at the relevant period the General Manager of the area was the Chief Mining Engineer and he conducted the enquiry fairly and properly and in accordance with the principles of natural justice. He has been cross-examined at length and has denied that the chargesheet Ext. M-1/5 and its original was not available in the office. He did not remember that if he had considered the FIR lodged by the concerned workman against B. M. Lal on 10-6-85 and there was any biasness against the workman in representing Sri Lal as management's presenting officer and no objection was raised by the workman against the procedure in the enquiry. The documents were not examined by the handwriting expert about fabrication of the same. He denied that he prevented the workman to examine the witness and he denied that he overlooked the cogent evidence in the

enquiry and he further denied that he acted unfair and improper manner.

9. No witness was examined by the workman during the preliminary enquiry and when the case was fixed for hearing argument on preliminary point it is clear from order dated 6-9-96 that Sri J.P. Singh, Advocate, appearing for the workman, conceded that the domestic enquiry was held fair and proper. Thereafter the matter was to be heard on merit and no further evidence was led by either side in support of their respective contentions.

10. While arguing it is submitted on behalf of the workman that holding of domestic enquiry was not fair and proper and as he was member of the union, namely, Colliery Karmachari Sangh functioning in the area and had protested against the action of the management and also organised demonstrations for fulfilment of the demands of the workmen, he was implicated in a case of fake appointment and false chargesheet was issued against him alleging misconduct of theft, fraud or dishonesty. It is also said that criminal case was filed for the same occurrence by the management and he was put under suspension and kept under suspension for long period of four years and when represented the matter for the management the domestic enquiry was held in quite haste and even conclusion of the trial case was not awaited by the Enquiry Officer where he was acquitted against all the charges. But he was held guilty in the departmental enquiry without any valid evidence on record and Sri B.M. Lal, Presenting Officer was biased against him as the workman had filed FIR against him for the same incident and altercation took place amongst them.

11. It was also pointed out that the concerned workman was not appointing authority. He was simply Typist-cum-Clerk and typing which was given to him for typing work officially and similar typewriter with similar key board are available in the market and it cannot be said that so called forged appointment letters were typed and issued by the concerned workman and even without ascertaining this fact he was chargesheeted and put under suspension and on the basis of enquiry report he was dismissed from service as the management was pre-determined to get rid of him arbitrarily and illegally. It is also said that when for the same occurrence criminal case was going on in the Court the parallel enquiry should not have been held by the management and the result of the criminal case ought to have been awaited by the management where he was acquitted of the charges levelled against him. It is said that there was no merit at all in the plea taken by the management and he has been victimised arbitrarily and dismissed from service with no fault of his and he is entitled for his reinstatement in service with full back wages and his demand is quite justified.

12. However, it has been argued on behalf of the management that fairness of domestic enquiry has been conceded on behalf of the workman vide order dated 6-9-96 and the only point to be considered in this case is about quantum of punishment awarded to the workman. It is further submitted that even in course of hearing on the preliminary

point of fairness and propriety of domestic enquiry no witness was examined on behalf of the workman nor any document was produced to show that there was any biasness against the workman or that the enquiry was not held fairly and properly. So far only allegation raised by the workman in his written statement is that Sri B.M. Lall who was Presenting Officer of the management was biased against the workman had filed criminal case against him that some altercation took place amongst them. However, it is pointed out that this domestic enquiry was started in July 1983 and on several occasions time petition was filed by the workman on the ground that criminal case was pending for the same occurrence and it should be disposed of. So far filing of criminal case against Sri B.M. Lall by the workman is concerned it is submitted that this enquiry is of the year 1983 whereas the workman had filed case against Mr. Lall in June 1985 just to intimidate him so that he did not produce management's witnesses against the workman or that he did not take active participation in the said domestic enquiry and this is another instance of misconduct of the workman and it is incorrect to say that Sri Lall was biased and prejudiced against the workman from before as the said criminal case filed by the workman was well thought of plan to intimidate at belated stage of enquiry.

13. It is also submitted that another plea has been taken by the workman that he was simply typist-cum-clerk and he was not appointing authority so as to issue appointment letter to some other workmen. True it is that he was not an appointing authority but he connived with Sri R.P. Singh and provided all the facilities for typing out forged appointent letters and prepared false and fabricated documents and had taken those letters and placed before the authorities and conspired with Sri V.R. Singh, the then Dy. Personnel Manager, incharge of the Establishment and got the said letters accepted by him as genuine and he accompanied the workers to the places of posting and he handed over those letters to those officers and he wrote joining letters on behalf of the workmen and after their signatures they were allowed to report. In this view of the matter it is submitted that his misconduct of getting basic letters fabricated with forged signature and used the same as genuine and getting persons recruited can't be disputed and the Enquiry Officer has rightly held him guilty of misconduct of charges levelled against him. This being serious misconduct, the quantum of punishment in the form of dismissal was quite legal and justified.

14. It is also pointed out that the workman had taken the plea that he was active office-bearer of the union called Colliery Karmachari Sangh and he incurred the displeasure of the management due to his union activities and he was charge-sheeted and involved in the case. But it is pointed out that on perusal of the reference it would appear that dispute was raised under Sec. 2A of the I.D. Act by the concerned workman himself in the year 1990 and the said Colliery Karmachari Sangh union did not sponsor the case nor any dispute was raised on behalf of the union and it goes to prove

that the union to whom he claimed to be office-bearer, was fully convinced about his serious misconduct and the said union did not raise the dispute on behalf of the workman. It is also submitted that it has been argued on behalf about fairness of enquiry that no proper opportunity was given and it was against principle of natural justice. But all these points go away in view of the fact that it has been stated on behalf of the workman that the domestic enquiry was fair and proper and now it is not open for him to challenge the same.

15. Another plea taken on behalf of the workman is that the criminal case was filed against him for the same offence and in that case he was acquitted by the Special Magistrate by his judgement dated 29-8-1986 but even then the management dismissed him from the service. In this regard it is submitted that criminal trial is quite different from the principle of domestic enquiry and in the criminal case the charge has to be established beyond all reasonable doubts and all the elements associated with the offence must be conclusively proved and that this workman forged the signature of Sri R. P. Singh and actually fabricated the documents and he might have got benefit of doubt. But while considering the charge of misconduct and dishonest act in domestic enquiry hearing the charge is to be established on the preponderance of evidence and sufficient evidence was led before the Enquiry Officer to show his active participation in fabrication of document forging signatures of Sri R. P. Singh and commission of his honest act of procuring false and fabricated appointment letters and pursuing the matter and getting those persons appointed would have been considered as serious misconduct. Therefore it was submitted that even the workman being acquitted in criminal case it might not have no bearing with the disciplinary proceeding and the action initiated in both the cases are different in nature. It is also submitted that after domestic enquiry being conceded as fair and proper under provision of Section 11-A of the Act the Tribunal is to see that the evidence led before the departmental enquiry or not and no fresh evidence is to be taken into consideration by the Tribunal and any award on such fresh evidence would be in violation of the provision to Section 11-A of the I.D. Act.

16. It is also submitted that the present case is to be considered in a very narrow campus that whether the charges have been proved or not and whether the punishment imposed upon the workman was disproportionate to his misconduct or not. It is submitted that the domestic enquiry being conceded fair and proper by the workman there is nothing to challenge the finding of the Enquiry Officer about finding the workman guilty for the charge of misconduct levelled against him and it was also submitted that the workman was found guilty of serious misconduct of dishonesty in connection with employers business and in this view of the matter punishment of dismissal imposed upon him was fully justified.

17. After going through the case and considering the points of arguments advanced on behalf of the parties, I find much force in the plea taken on behalf of the management

that both the criminal cases and departmental proceedings are on different footing and certainly in a departmental enquiry the charges are to be established on preponderance of evidence and the workman can be found guilty for the charges even after acquittal of criminal case where the charges are to be established beyond all reasonable doubts in absence of that an accused got benefit of doubts whereas in a departmental proceeding the matter is to be considered in the light of circumstances and the evidence on record. It is clear that the workman got extra interest in appointing of those workman in connivance with Sri V. R. Singh, the then Dy. Personnel Manager Incharge of establishment and got those forged and fabricated appointment letters accepted by him as genuine and he accompanied the workmen from place to place and to their place of posting and he handed over those letter in the offices where he wrote joining letters on behalf of those workmen and after getting their signatures got them allowed to report for duty. From this count of eye witness and document proved produced in the departmental enquiry the Enquiry Officer has rightly held him guilty for the misconduct of dishonesty and fraud in respect of employer's business fully proved and established and he found him guilty for the above misconduct as given in the charesheet. It is also to be noted here that certainly the workman got the departmental enquiry forged for such a long period on the pretext that criminal case was pending against him and that in course of pendency of the criminal case he got criminal case filed against Sri B. M. Lall, Presenting Officer of the management just to threaten him so that he would not dare to produce evidence both oral and documentary against him in the enquiry and this is another instance of misconduct of the workman and now he has taken the plea that Sri Lall was biased against him and the management knowingly appointed him Presenting Officer in the said departmental enquiry whereas the fact is otherwise as noted above.

18. After considering all the facts and documents marked exhibits on behalf of the parties in course of hearing on preliminary point I find no merit in the plea taken by the workman in the demand of his reinstatement in service with full back wages and certainly his demand is not justified at all and he is not entitled to any relief as claimed. Both the points are decided against the workman.

19. Hence, the award—

The demand of the concerned workman, Manoj Kumar Sinha, for reinstatement in service with full back wages is not justified and he is not entitled for relief as claimed.

However, there will be no order as to cost.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का. आ. 1320.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, इलाहाबाद के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर 1096GI/97—9

के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. -41012/124/93-आई. आर. (बी.)]

के. बी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1320.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on 23-4-97.

[No. L-41012/124/93-IR(B.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 47 of 1995

In the matter of Dispute:

BETWEEN

Divisional Railway Manager,
Northern Railway,
Allahabad Division,
Allahabad.

AND

Dina Nath,
Mandal Sangthan Mantri,
Uttar Railway Karmchhari Union,
2, Naveen Market, Prade, Kanpur.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. 41012/124/93-I.R.(B) dated 3-5-1995 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

KYA PRABHANDH TANTRA MANDAL RAIL PRABANDHAK UTTAR RAILWAY ALLAHABAD DWARA KARMKAR SHRI MOINNUDDIN KO 16-8-1986 SE SEWA SE NISHKASHIT KARNA NAYOCHIT HAI ? YADINAH TO SANBANDHIT KARAMKAR KIS ANUTOSH KA HAKDAR HAI ?

2. It is needless to give the detail of the case as on 11-3-1997 the concerned workman had given in writing that during the pendency of reference management has given job and does not press the reference.

3. In view of above the demand of concerned workman having been already met the reference is decided accordingly.

Sd/-

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का. आ. 1321.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, इलाहाबाद के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-41012/75/91-डी.-2(बी.)/आई. आर. बी-1]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1321.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on 23-4-97.

[No. L-41012/75/91-D-2(B)/IR(B-I)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 47 of 1992

In the matter of Dispute:

BETWEEN

President,

Rashtriya Chaturtha Shreni Rail Mazdoor Congress,
1/236 Namneir, Agra.

AND

Divisional Railway Manager,

Northern Railway,
Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-41012/75/91-D-2(B) dated 26-2-92/4-3-1992 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether Divisional Engineer, Northern Railway, Tundla was justified in terminating the services

of Shri Rajveer Singh S/o. Sg. Genda Lal as CPC Gangman w.e.f. 5-1-90 ? If not what relief the workman is entitled to ?

2. The case of the concerned workman Rajveer Singh is that he was a casual labour PW1, Northern Railway at Tundla from 1974. After completing 120 days he had acquired temporary status. He continued to perform this duty. On 5-1-90 he was removed from service as in the medical examination he was declared unfit for B-1 category but was found fit for G-1 and G-2 category and thus he ought to have been given the post of Chaprasi Chowkidar, Waterman Messenger etc. As he had completed more than 240 days he ought to have been given retrenchment compensation and notice pay. In its absence this retrenchment is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which the claim of the concerned workman has been denied.

4. From the own admission of the concerned workman it becomes clear that he was a temporary employee and that he was found medically unfit and was consequently decategorised. His grievance is that he has not been given alternative job. This claim of the concerned workman stands completely negated by the case of Union of India versus A Mouzi 1996 Lab. IC 2649. In this case a temporary employee was decategorised because of eye's problem. No suitable job was offered to him. Interpreting the various provisions of railway establishment Code Hon'ble High Court was pleased to observe that in a case of temporary employee if medical unfitness has occurred due to performance of duty the management is duty bound to provide alternative job otherwise it is not obligatory on the part of the railway. In the case of concerned workman medical incapacity has not occurred due to act done during the course of performance of duty. Instead it has occurred due to again and this is not connected with employment. Had the incapacity arises due to any accident while performing the duties the position would have been different. Thus in view of above ruling I come to the conclusion that it was not obligatory on the part of the opposite party to have provided alternative job to the concerned workman.

5. I am further of the view that where the employee is removed from service due to medical unfitness it would not be a case of retrenchment, hence various provisions of Industrial Disputes Act, including 25F of I.D. Act would not attract.

6. In view of above discussion my award is that the action of the management in terminating the services of the concerned workman is justified. Consequently, the concerned workman is not entitled for any relief.

7. Reference is answered accordingly.

Sd/-

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का.आ. 1322.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, लखनऊ, के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-41011/68/92-आई.आर. (डी.यू.)/बी-1]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1322.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Awards of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railways, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on 23-4-97.

[No. L-41011/68/92-IR(D.U.)/B.I.]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

Before Shri B.K. Srivastava Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Deoki Palace Road, Pandu Nagar, Kanpur.

Industrial Dispute No. 114 of 1993

In the matter of Dispute between :

D.R.M.

Northern Railway,

Hazratganj, Lucknow

AND

Working President,

Railway Karmchhari Union,

96/196 Roshan Bajaj Lane,

Ganeshganj, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. 41011/68/92 I.R. (D.U.) dated 16-12-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

Whether the action of Divisional Railway Manager, Northern Railway, Lucknow in not fixing the pay of S/Shri Mangroo Ekka, Vijay Tirki, Jurng Bhagar, Bahauran Bhagar and Mangre Bhagar at Rs. 1500/- on 16-3-78 as H.S. Fitter Grade-I and also not promoting them as F.I.C. from May, 1991 is justified? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?

2. It is not necessary to give details of the case as on 12-3-97 Au. Rep. of the workman made an endorsement as not press the case. Hence the reference is answered against the concerned workmen for want of prosecution and proof and concerned workmen are not entitled for any relief.

B.K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का.आ. 1323.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, टुंडला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-41011/55/90-आई.आर. (डी.यू.)/बी.1]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1323.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Tundla and their workmen, which was received by the Central Government on 23-4-97.

[No. L-41011/55/90-IR(D.U.)/B.I.]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

Before Shri B.K. Srivastava, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour Court, Deoki Palace Road, Pandu Nagar, Kanpur.

Industrial Dispute No. 150 of 1991

In the matter of Dispute between :

Asstt. Engineer,

Head Quarter,

Northern Railway, Tundla.

AND

President,

Rashtrya Chhaturth Shreni,

Rail Mazdoor Congress,

Agra.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide its notification No. 41011/55/90 I.R. (D.U.) dated 18-9-91 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:

Whether the Asstt. Engineer, Northern Railway, Tundla is justified in terminating the services of Shri Khubi Ram w.e.f. 16.7.78, Shri Pratap Singh w.e.f. 6.5.84 and Shri Dinesh w.e.f. 6.5.84? If not, what relief the workmen concerned are entitled to?

2. In this reference there are 3 workmen viz. Khubi Ram, Pratap Singh, and Dinesh. The case of Khubi Ram is that he worked from 13.3.76 upto 27.7.77 for 294 days. His services were brought to an end without payment of retrenchment compensation and notice pay. Hence it is bad in law. Pratap Singh worked from 29.1.77 upto 6.5.84 where as Dinesh had worked from 21.6.78 to 6.5.84. They had completed more than 240 days in a year. Yet their services were terminated without notice pay and retrenchment compensation which is bad in law.

3. In reply the management has not denied that either of the 3 workmen had not completed 240 days in a year. Instead their case is that Khubi Ram worked for 323 days from 13.3.76 to 15.7.78, where as Pratap Singh worked as casual Khalasi in broken period for 1290 days between 29.1.77 to 5.5.84. Dinesh had worked for 770 days. Further all of them had stopped coming office themselves. They were not removed from service.

4. In support of their case Khubi Ram WW-1, Pratap Singh WW-2 and Dinesh Singh WW-3 have examined themselves. There is no evidence in rebuttal hence I accept and hold that the concerned workmen had completed more than 240 days in a year. It is further held that they had not abandoned the job as the railway has not adduce any evidence to prove this fact.

5. There is no dispute that none of the concerned workmen have been paid notice pay and retrenchment compensation. Hence their termination is bad being in breach of Section 25F, I.D. Act.

6. Still my award is that Khubi Ram will not be entitled for any relief as his reference is more than 12 years old and there is no explanation for in delay in case of Balwant Singh V/s P.O. Labour Court Bhatinda LAB I. C. 1996 (415) it has been held that no relief shall be granted. Hence Khubi Ram will be not entitled for any relief. My further award is that concerned workmen Pratap Singh and Dinesh will be as casual worker entitled for reinstatement with back wages from the date of reference on which they were drawing wages for the last time.

B.K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का.आ. 1324:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. (टी.), वाराणसी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-40012/70/91-आई.आर. (डो.यू.)]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1324:—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O. (T), Varanasi and their workman, which was received by the Central Government on 23-4-97.

[No. L-40012/70/91-IR(D.U.)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

Before Shri B.K. Srivastava, Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal Cum Labour Court, Pandu Nagar Kanpur.

Industrial Dispute No. 188/91

In the matter of Dispute between :

Sri Virendra Pratap Singh Yadav

S/o Sri Achhe Lal Yadav

C/o Sri N.C. Pandey Z-323, G.T.V. Nagar, Kareli, Allahabad.

AND

S.D.O. (T)

Bhadohi District Varanasi.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, vide its notification No.L- 40012/70/91 I.R. D.U. dated 19.11.91 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of SDO(T) Bhadohi District Varanasi in terminating the services of Sri Virendra Pratap Yadav S/o Shri Achhe Lal Yadav casual labour w.e.f. 16.3.89 is justified? If not, what relief he is entitled and from what date?

2. The concerned workman Virendra Pratap Singh in his claim statement has alleged that he was engaged by the opposite party on 1.1.84 as casual labour and he worked upto 26.9.89. Atleast in one year preceding the date of termination he had completed 240 days. Hence his retrenchment without paying notice pay and retrenchment compensation as required by Sec. 25F of I.D. Act is bad in law.

3. The opposite party had filed written statement in which it is not denied that the concerned workman was engaged as daily rated casual labour on 1.11.84, by SDO Telephones at Azamgarh. Later on the concerned workman's services were required at Bhadohi Varanasi Telecom District due increase of work. The concerned workman in terms of circular dated 24.2.86 issued by Director General Telecom was brought at this place from November 1987. Thus his re-employment at Bhadohi, Varanasi was a short gap arrangement. Later on his employment was extended from month to month upto 25.3.89 when the work at Varanasi

Bhadohi came to an end and he was diverted to Azamgarh for further employment. It is also alleged by the management that the Telecom Department is not an industry.

4. In the rejoinder new factual pleas raised in the written statement have been denied.

5. Thus from the pleadings of the parties it becomes clear that atleast from November 1987 the concerned workman was employee of the SDO Telecom Bhadohi and worked upto 25-3-89, on the basis of extension of service from time to time. Thus also it becomes clear that he had completed 240 days in a year. Indeed this fact has also been proved by the concerned workman. In rebuttal there is evidence of J.P. Jaiswal M.W.I Section Supervisor. In his evidence he has admitted that from November, 1987 to July 1988, the concerned workman had completed 278 days and from August 88 to March, 89, he had completed for 237 days. Thus it is established both from the pleadings and evidence that the concerned workman had completed for more than 240 days before retrenchment. It is also not disputed that no notice pay and retrenchment compensation was given. Even if the version of the management is correct that pressure of work having been reduced the services of the concerned workman were not required, still there was need for compliance of section 25F of I.D. Act. Hence, I have no hesitation in coming to conclusion that retrenchment of the concerned workman is bad.

6. Lastly the objection of the management regarding Telecom Department being industry may be taken up. It may be mentioned that this point was treated as preliminary issue and was decided against the management vide finding dt. 2-1-96 which shall form part of the award.

7. Accordingly my award is that termination of the concerned workman is bad in law and he is entitled for reinstatement with full back wages at the rate at which he was drawing wages for the last time. It will be still open to the management to retrench the concerned workman if actually there is no work but for this they have to comply with the provisions of Sec(s) 25F and G of I.D. Act.

8. Reference is answered accordingly.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 188/91

In the matter of Dispute:

BETWEEN

Shri Virendra Pratap Yadav

Versus

S.D.O.(T)

ORDER

1. In All the abovementioned industrial disputes referred to this tribunal under section 10(1) of Industrial Disputes Act, the dispute is regarding illegal termination of services of the workman. Inter alia, in all written statements Telecom Department had raised the plea that the telecom department does not fall in the definition of Industry. Consequently these references are bad in law. Hence a preliminary point has been culled out for decision. As it has been seen this point is common to all the reference it is being disposed of by the instant order which will govern the other cases

2. On behalf of telecom department reliance was placed on the case of Achaibar Lal versus Union of India decided by Central Administrative Tribunal, Allahabad, on 11-9-90, in which following observations of the case of Sakhte Lal versus Union of India O. A. No 675 of 1982, it was held that telecom department was not an industry. But no reasons were given for arriving at this conclusion. As regards the case of Sakhte Lal (Supra) the certified copy of the same is before me. I have gone through this judgment. In this case the dispute was regarding the Extra-Departmental Personnel of Post Office. It was held that Post Office was not an Industry. The point regarding Telecom Department was not even remotely considered. On the other hand reference may be made to the case of D.N. Banerjee versus P. K. Mukherjee AIR 1953 SC 58. In this case the dispute was in respect of Municipal Board being an industry or not. While examining this preposition, the Hon'ble Supreme Court had given example of Telephone Department as well. It was observed that in case telephone service was rendered by a private person or corporation, there can be no manner of doubt that it would be an industry. It was further observed that if it was run by public body like Municipal Board etc., even then it would be an industry. It is true that question of telephone department which is at present known as telecom department was not the subject matter of issue. In that case still this observation should be taken as obiter dicta of Hon'ble Supreme Court. There can not be two opinion that even a obiter of Hon'ble Supreme Court is binding on all Courts and Tribunals. Hence respectfully following the abovementioned obiter the case of Central Administrative Tribunal referred to on behalf of Telecom Department should not be followed. Hence the very foundation of objection of Telecom department stands demolished.

3. Even if we independently examine the question of industry vis a vis other provisions of Industrial Dispute Act, we will reach the same conclusion. Sec 22 of Industrial Disputes Act, prohibits an employee of public utility service from going on strike without giving notice. Similar duty is casted on the employer. Section 2—defines Public Utility Service. It includes Telecom Department as well. If it was the intention of the legislature to exclude Telecom Department from the operation of the Industrial Disputes Act, it would have not included it in the Public Utility Service.

4. In the celebrated case of Bangalore Water Supply and Sewrage Board versus A Rajjappa 1978(36) FLR 266 triple test were laid down for examining if any organisation was an industry or not. In the above case following tripple test was laid down for examining whether or not any organisation is an industry.

- (i) Systematic activity;
- (ii) organised by co-operation between employer & employee (the direct and substantial element is chemical); and
- (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss), prima facie, there is industry in the enterprise.

There can be no manner of doubt that Telecom Department while extending facility of Telephone is rendering services to the public at large and that too for considerations. It is a systematic activity. Further there is organised cooperation between the management and the employee. Obviously this service cannot be carried by the management without the active cooperation of employees. Hence, I have no manner of doubt that having examined the Telecom Department on the anvil of tripple test, it should be held as industry.

Now there is no controversy left that Telecom Department is covered by Consumer Protection Act. It in turn would go to show that while rendering service Telecom Department does not discharge so called sovereign function. In my opinion, it is an additional ground for holding that Telecom Department for extending telephone facility for public at large as an industry.

In the abovementioned case of Bangalore Water Supply and Sewerage Board versus A Rajjappa (Supra) it was also held that if the provisions of Article 309 to 311 of Constitution of India, were applicable to any civil servant such servant, organisation to which such civil servant belongs, would not be included in the definition of industry. Telecom Department is a statutory body. Article 309 to 311 of Constitution do not apply to its employee. No rules have been brought to my notice which may exclude the operation of provisions of Industrial Disputes Act, to the servants of Telecom Department. Hence on this score the Telecom Department cannot be thrown out from the ambit of **Industry**. I am further of the view, that even if there would have been any rules still temporary, adhoc or muster roll employee would still be governed by the provisions of Industrial Disputes Act, as they cannot be classified as Civil Servants.

It may also be noticed that in the case of B. Lalithakumari versus Divisional Engineer (Cables) Telephones District Vellayambalam Trivendrum, 1984 (49) FLR 57 it has been held that Telephone Department is an Industry. It was a specific case of an employee of Telephone Department. Objection was raised with regard to that

Telephone Department not being an Industry. The same was overruled and it was held that Telephone Department is an Industry. Thus this ruling further lends support to the conclusion that Telecom Department is an Industry and as such reference is not vitiate.

Lastly reference may be made to the case (1991) 15 Administrative Tribunal Cases 531. In this case CAT had held that provisions of Chapter V-A of Industrial Disputes Act, 1947, applies to Post and Telecom Department. Thus by implication means that employees of these departments would be covered by the provisions of Industrial Disputes Act. Unless this department is held to be an industry, how can these provisions could be made applicable to the Department of Telecom.

In view of foregoing discussions, objection of Telecom Department is overruled and it is held that Telecom Department is an Industry and as such reference is not vitiated on this score.

Dt. 2-1-1996

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का. आ. 1325:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नो. ई. रेलवे, लग्ननऊ के प्रबंधन के संबंध निर्योजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-41012/29/91-आई. आर. डी. यू./बी.।]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1325:—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Awards of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of N E Railways, Lucknow and their workman, which was received by the Central Government on the 23-4-97.

[No. L-41012/29/91-IRDU/B I.]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE
ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 195/1991

In the matter of Dispute between
Senior Divisional Electrical Engineer
N. E. Railway
Ashok Marg, Lucknow

AND

General Secretary
N. E. Railway Sharmik Sangh
6, Naveen Market,
Kaisarbagh, Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-41012/29/91 I. R. (D.U) dated 19-11-91 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the Senior Divisional Electrical Engineer, N. E. Rly., Lucknow is justified in terminating the services of Shri Maharaj Dutt Yadav s/o Sh. Salikram, as casual Labour w.e.f. 1-1-86 ? If not what relief he is entitled to ?

2. The case of the concerned workman Maharaj Dutt Yadav is that he was engaged from 25-9-83 by Senior Divisional Electrical Engineer and worked there as a casual Labour. From 18-4-85 upto 31-12-85 he has completed more than 240 days by working continuously. Yet he has been removed from service without payment of notice pay and retrenchment compensation. In this way his retrenchment is bad being in breach of Section 25F I. D. Act.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that from 18-4-85 to 31-12-85 he has worked for 258 days. He was removed from service as he was taken in service without approval of General Manager and proper screening.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. From the pleading of the parties it become clear that the concerned workman had worked for more than 240 days in a year between 18-4-85 to 31-12-85. Hence before retrenchment he was entitled for benefit of Section 25F I.D. Act. Admittedly no retrenchment compensation and notice pay has been given to the concerned workman. Hence his retrenchment is bad in law.

6. Simply the fact that the concerned workman was not appointed with approval of General Manager or Screening could not be any ground for removal from service outrightly. Even in such a case compliance of provision of Section 25F I.D. Act was necessary.

7. In view of above discussion my award is that termination of concerned workman is bad in law and he is entitled for reinstatement as casual labour from the date of reference @ at which he was drawing wages for the last time.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1997

का. आ. 1326.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 23-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/186/93-आई. आर.बी. 2]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd April, 1997

S.O. 1326.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhartiya State Bank Kanpur and their workman, which was received by the Central Government on the 23-4-97.

[No L-12012/186/93-IRB. 2]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 112 of 1993

In the matter of Dispute:

BETWEEN

President
State Bank of India Karamchari Sangh
K-46 Devendrapuri Kidwai Nagar
Kanpur.

AND

Regional Manager
Bhartiya State Bank
Region III The Mall
Kanpur.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification no. L-12012/186/93 —I R. B-2

dated 15-12-1993, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal.

Whether the action of the management of State Bank of India, Kanpur, in refusing full wages to Sri Vijay Kumar, Sweeper-cum-Farash, is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled to ?

2. The case of the concerned workman Vijay Kumar is that he was appointed as permanent part time sweeper on 26-12-77 by the opposite party State Bank of India at Navin Market Branch, Kanpur. Earlier he was getting 1/3rd salary. It was raised to 1/2 w.e.f. 16-10-81. It was further enhanced to 3/4th w.e.f. 1-1-1985. Subsequently the branch manager of the bank wrote to the Regional Manager to give him full time wages as the work load had increased. But the same was refused. As the concerned workman is doing work for whole time every day, he is entitled for full wages.

3. The opposite party has filed reply in which raising wages upto half of the salary is not disputed. It is also admitted that the branch manager has raised salary of the concerned workman to 3/4th but the same was not approved by the Regional Manager as the number of working hours has not increased and further the area for which he was engaged for sweeper had also not increased. Hence, he is not entitled for whole time wages. It is also alleged that the claim is barred by principles of Resjudicata.

4. In the rejoinder it has been denied that work load has not been increased.

5. There is para 4.5 of First Bipartite Settlement which regulated the increase of wages of a part time workman. According to this para if a workman works for more than 29 hours in a week he becomes entitle for full scale wages. Thus in the instant case it is to be seen if the concerned workman had worked for more than 29 hours a week.

6. Vijay Kumar W.W. 1 has stated that he used to work more than 29 hours per week, some times work of peon was also being taken from him. In his cross examination he had admitted that he was engaged for sweeping only and the area of the bank for which he was engaged for sweeping has not increased.

7. Branch Manager Santosh Tiwari M.W. 1 has stated that the concerned workman was engaged to sweep 1780 Sq. Fit of space. That area has not increased. The concerned workman works only for 18-19 hours in a week.

8. In this case there are papers which clinch the issue in favour of the workman. There is a letter dated 17-10-88 issued by the branch manager to the concerned workman by which an explanation has been sought from the concerned workman as to why he did not report on duty from 12.00 noon to 17 p.m. Apart from this there is letter dated 30-6-85, written by branch manager to Regional Manager informing that the volume of work of the concerned workman had increased in many fold and his claim for whole time claim is justified. The Regional Manager had refused to grant this request. Be

that as it may from these two papers it becomes clear that concerned workman had been atleast working for 7 hours a day and if we calculate for the number of hours even for five days it will be 35 hours in a week. Hence, I accept the contention of the concerned workman and hold that he had been working for more than 29 hours a week. Therefore, in terms of para 4.5 of bipartite settlement, the concerned workman will be entitled for full time wages.

9. It is the objection of the management that the area of rented building in which the bank is housed has not increased. It is immaterial. The question of whole time wages is to be decided on the basis of number of working hours of a workman in a week.

10. In the end my award is that the concerned workman had been doing work for more than 29 hours in a week as such he is entitled for full wages from the date of reference.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1327.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार साउथ सेन्ट्रल रेलवे, मिकन्दराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण-1, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-41012/107/94-आई.आर. (बी.आई.)]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April, 1997

S.O. 1327.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal I, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of South Central Railway, Secunderabad and their workman, which was received by the Central Government on the 24-4-97.

[No. L-41012/107/94-IR (B I.)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

Present: Sri V.V. Raghavan, B.A., L.L.B., Industrial Tribunal-I.

Dated : 6th day of March, 1997.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 83 OF 1995

Between

Shri Mehtab Patel S/o Shri Masthan Patel, Ex. Rly. Hamal, Tandoor, Old Tandur (R.R.Dist.) P.I.N 501 141 (A.P.)

..Petitioner

AND

The Sr. Divl. Commercial Superintendent,
Secunderabad (B.G.) South Central Rly.,
2nd Floor, Sanchar Bhawan, Secunderabad

..Respondent

Appearances : S/Sri B. Narasimha Sharma and M.C.
Jacob, Advocates for the Petitioner
Shri A.K. Jayaprakash Rao, Advocate for
the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi made a reference to this Tribunal by its Order No. L-41012/107/94-IR (B.I.) Dt. 7-8-1995 under Section 10 (1)(d) & 2A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of Industrial Dispute mentioned in its Schedule which reads as follows :

“Whether the Railway Administration is justified in terminating the services of Shri Mehtab Patel without assigning any reasons? If not, to what relief the workman in dispute is entitled for?”

2. The workmen filed a Claims Statement contending as follows:

The petitioner-workman was a hamali working at Tandur Railway Station in Secunderabad (BG) Division of south Central Railway. He was engaged in loading and unloading of parcels and other materials in and from the trains. He should be available on the platform when loading and unloading work has to be done. He has to unload the parcels from the train and carry them to parcel office. He is paid as per the weight. The Station Superintendent of Tandur Railway Station will prepare a monthly statement as per the weight loaded and unloaded by the petitioner and other hamalies and submit the same to the Sr. Divl. Commercial Superintendent, Secunderabad, who in turn will send a Pay Order to the Station Superintendent to pay the amount to the petitioner and other hamalies. The Labour Enforcement Officer visited Tandur Railway Station on 14-11-1991 and found the petitioner and other hamalies are not paid minimum wages and sent a letter to the Station Superintendent, Tandur Rly. Station and Sr. Divl. Commercial Superintendent, Secunderabad to pay the minimum wages to the petitioner and other hamalies. The Sr. Divl. Commercial Superintendent (Respondent herein) instructed the Station Superintendent of Tandur Railway Station to give a Complaint to the Government Railway Police and also the Railway Protection Force to the effect that unauthorised persons are handling parcels/luggage booked at the station and they should be prevented from doing so. Accordingly the Station Superintendent lodged a complaint on 24-4-1992 and since then the petitioner and other hamalies were not permitted to enter into the Railway Station to perform their duties which is illegal and violative of provisions of I.D. Act. The petitioner-workman was working as a Hamali

for the last 20 years. No reason is given for terminating his services. The respondent refused to reinstate the petitioner before the Conciliation Officer. So this reference is made. On a complaint given by the Labour Enforcement Officer to the Regional Labour Commissioner, Central, the authority under the Minimum Wages Act, passed an Award, dt. 14-8-1993 in Application No. 18/93 and directed the respondent to pay minimum wages to the petitioner and other Hamalies. Then the respondent moved the matter before the Hon'ble High Court which is pending. The respondent may be directed to reinstate the petitioner with full back wages and other consequential benefits.

The respondent filed a counter contending as follows :

The Petitioner was not appointed by the Respondent. The Petitioner's name does not find a place in the Attendance Register or any other registers of the respondent. So he is not the employee of the Respondent. Under the provisions of 2302 of IRCM Volume-II the Station Master is entitled to engage Hamalies. Accordingly, the Station Master at Tandur engaged the petitioner and other Hamalies as Sowcari Hamalies for loading and unloading for early clearance of the parcels when there is heavy work. The Bill is to be submitted by the Hamalies. When Station Master submits the Bill, the respondent issues pay Orders. The Hamalies are paid at the rate of Rs. 18/- for 100 quintals towards hamal charges for handling the packages. The petitioner approached the Regional Labour Commissioner claiming minimum wages and also for the designation. There is no evidence that the petitioner is working since 20 years. He is not entitled for minimum wages as the Tandur Railway Station is not notified as Scheduled Employment. Hence the petitioner is not entitled to any relief.

4. The workman examined himself as M.W. 1 and filed Exs. W1 to W13. The Traffic Inspector of Tandur Railway Station is examined as M.W. 1 and he filed Exs. M1 to M6.

5. The points for consideration are :

- (1) Whether the petitioner is a workman within the meaning of I.D. Act.
- (2) To what relief?

6. POINT No. 1 : —The admitted or proved facts are as follows :—There are 3 Parcel Porters appointed on regular basis on monthly wages in Tandur Railway Station. They work in shifts. Their duty is to carry the parcels from the Parcel Office of the Railway Station and load them into Compartment of passenger train called S.L.R. for transport. They are also to unload the parcels from the S.L.R. and carry them to the Parcel Office for delivery to the consignees. All these parcels are carried in a Passenger Train. The loading and unloading of the parcels etc., into Goods Train at Tandur Railway Station was stopped about 7 years back. The Passenger Trains stop for two minutes only at Tandur. In this two Minutes, a single regular parcel porter is unable to load the parcels for being carried to other places and unload the parcels that are to be delivered to the consignees at Tandur Rly. Station. The Railway Administration by Rule 2302 IRCM

Vol. II permitted the Station Masters to engage Hamalies to assist the regular Parcel Porters for this purpose. These Hamalies engaged by the Station Master locally are called as "Sowkari Hamalies". These Hamalies are paid at a fixed rate on the quantity of parcels carried by them. They were paid at the rate of Rs. 18 per 100 quintal from October 1986 and Rs. 22 per 100 quintal from 1-5-1993 as can be seen from Ex. W1 Proceedings dt. 28-4-93 of the Divl. Railway Manager (Commercial).

7. The petitioner (Mehtab Patel), Vazeer Patel and Yellappa have been acting as Sowkar Hamalies since more than 20 years. M.W. 1 the Traffic Inspector who has been working at Tandur Rly. Station since about 20 years in different capacities, admitted that these three persons have been working as Sowkar Hamalies. Sowkar Hamalies have to submit the bill to the Traffic Inspector who in his turn checks the bill with reference to the Parcels carried and forward the same to the Divl. Commercial Supdt., Secunderabad. The Sr. Divl. Commercial Superintendent passes the Bill and sends a Pay Order and then the amount is paid to all these three persons by taking their acknowledgements. Exs. W1, M1 and M2 are the returns of goods handled by the Sowkar Hamalies in which the quantity of parcels carried by these people in a particular month are shown. Ex. W2 is a covering letter sent to the Station Superintendent by the Divl. Railway Manager. The amount is paid to the Sowkar Hamalies by taking their acquittance. Ex. W3 is such a document. The amount is paid to the petitioner, and other two Hamalies as per Ex. W4.

8. While so the Labour Enforcement Officer visited on 14-11-91 the Tandur Railway Station and found that the petitioner and another Sowkar Hamalies are not paid minimum wages. He sent a report to the Station Superintendent and Sr. Divl. Commercial Superintendent, Secunderabad instructing them to pay the minimum wages. They have not paid the minimum wages to the Hamalies. The Labour Enforcement Officer filed a case before the Regional Labour Commissioner (Central) for a direction for payment of minimum wages to the petitioner and other Sowkar Hamalies. The petitioner avers and deposes that to avoid payment of minimum wages to the petitioner and other Sowkar Hamalies, the Station Superintendent sent the original Ex. W5 letter dt. 24-4-92 (Ex. M6 is the copy) to the Acting C.S.R./Tandur complaining that the unauthorised persons are attending the SLR Compartment for handling the parcels/luggage and that these persons are demanding more money from the public who have come to the Station for booking parcels or luggage for loading and also from the public taking away the packages from the station after taking delivery from booking office. Thereby the Railway Protection Force and Govt. Railway Police prevented the petitioner and other Sowkar Hamalies from entering into the Station. The petitioner pleads that to avoid the payment of wages, they are prevented from entering into station and it amounts to termination of service.

9. M.W. 1 deposed that all these Sowkar Hamalies are demanding heavy amounts from the customers or consignees. The public have complained the same by a letter to the acting Commercial Supervisor and so the petitioner and other

Sowkar Hamalies are prevented from discharging the duties and receiving the hamali charges which they have been doing since more than 30 years at the Tandur Railway Station.

10. The main point in this dispute is whether these Sowkar Hamalies are the workman within the meaning of I.D. Act. These Sowkar Hamalies are not given any appointment order. They are not given Scales of pay and their attendance is not marked. There are no fixed hours of work. They are paid for the total weight of the parcels carried by them in a particular month fixed from time to time by the Railway Administration. They have to be present as and when a passenger train reaches the Railway Station. They have to load the parcels booked in Tandur Railway Station and unload the parcels from the Train for being delivered to the customers at Tandur Railway Station. The petitioner pleads that he is the workman of the railway whereas the respondent pleads that the petitioner is not the workman.

11. The learned counsel for the petitioner cited number of decisions in support of his contention. In DHARANGADHRA CHEMICAL WORKS LTD., APPELLATE v. STATE OF SAURASHTRA AND OTHERS RESPONDENTS (AIR 1957 S.C. 264). In this case the Agaries working in the Salt Works are professional Labourers and they themselves personally work alongwith the members of their families in the production of salt in the land of the company. They are held to be the workman under the I.D. Act, by the Supreme Court. In M/s. RADHAKRISHNA UMBRELLA FACTORY ALLEPPEY AND OTHERS, PETITIONERS v. INDUSTRIAL TRIBUNAL ALLEPPEY AND OTHERS (1971 LAB. I.C. 811) the Kerala High Court held that the Hamalies who unload the goods from the lorries and store them in the godown of the dealers are held to be workman though there are no working hours for them and though they are paid for the load handled by them. The Kerala High Court held the same view in CALICUT NORDUM SPG AND MFG. MILLS LTD. CHELAMBA. APPELLANT v. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALICUT AND ANOTHER RESPONDENT (1977 LAB. I.C. 1673). The Supreme Court held that the contract workers are also workmen in HUSSAINBHAI PETITIONER v. THE ALATHFACTORY TEZHILALI UNION AND OTHERS (AIR 1978 SC 1410). The learned Judge Hon'ble Sri Justice V. R. Krishna Iyer held as follows in para 5 of the Judgment.

"The true test may, with brevity, be indicated once again. Where a worker or group of workers labours to produce goods or services and these goods or services are for the business of another, that other is, in fact, the employer. He has economic control over the workers subsistence, skill, and continued employment. If he, for any reason, chokes off, the worker is, virtually, laid off. The presence of intermediate contractors with whom alone the workers have immediate or direct relationship ex contractor is of no consequence when, on lifting the veil or looking at the conspectus of factors governing em-

ployment, we discern the naked truth, though draped indifferent perfect paper arrangement, that the real employer is the Management, not the immediate contractor. Myriad devices, half-hidden in fold after fold of legal form depending on the degree of concealment needed, the type of industry, the local conditions and the like, may be resorted to when labour legislation costs welfare obligations on the real employer, based on Arts. 38, 39, 42, 43 and 43-A of the Constitution. The court must be astute to void the mischief and achieve the purpose of the law and not be misled by the maya of legal appearances.

The Madras High Court held in THE MANAGEMENT OF TRACTORS AND FARM EQUIPMENT LTD, PETITIONER v. THE PRESIDING OFFICER, 1ST ADDL. LABOUR COURT AND T.A. DOSS, RESPONDENTS (1983 LAB. I.C. 460) that the workers engaged regularly for loading the tractors in the Railway Wagons are the workmen. The Supreme Court held in M/S. SHINING TAILORS, APPELLANT v. INDUSTRIAL TRIBUNAL II, U.P. LUCKNOW AND OTHERS RESPONDENTS (1983 LAB. I.C. 1509) that Tailors working in piece rate basis in a big tailoring establishment are workmen.

12. The respondent did not cite any decision to prove that the petitioner is not the workman.

13. In view of the fact that the petitioner and two other workers have been continuously working in the Railway Station since 30 years and they are being paid a particular rate as Wage it has to be held that the petitioner is a workman within the meaning of I.D. Act.

14. Point No. 2 : In view of my finding on Point No. 1, the petitioner is entitled to be reinstated as Sowkar Hamali, with the same service conditions as are obtaining on 24-4-1992. He is entitled to wages at the rate fixed by the Railway Administration for the Sowkar Hamalies from time to time. The above direction with regard to the payment of wages is subject to the final decision of the Hon'ble High Court in the case under the Payment of Wages Act initiated by the Labour Enforcement Officer.

An award is passed accordingly.

Dictated to the Steno-typist, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 6th day of March, 1997.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal

Appendix of evidence

Witness examined for

Petitioner-Workman.

W.W. 1 : Mehtab Patel

Witness examined for the
Respondent-Management.

M.W. 1 : D. Anand Rao

Document marked for the Petitioner-workmen

Ex. W 1 : Xerox copy of return of goods handled by Sowkar Hamalies in Jan. 1991.

Ex. W 2 : Pay Order dt. 9-1-92 for Rs. 358 65 to the Station Master for paying the same to Hamalies.

Ex. W3 : Pay Order dt. 9-1-92 (Xerox copy).

Ex. W4 : Xerox copy of the amounts distributed to the Hamalies payable under Ex W2 and W3.

Ex. W5 : Letter dt. 24-4-92 addressed to the acting GSR and Railway Protection Force by the Station Master asking them not to allow the public for entering the Station and to handle parcel and luggage.

Ex. W6 : Summon sent by the RLC to WW1 and others Hamalies.

Ex. W7 : Order dt. 14-3-93 passed by the RLC in Application No. 18/93.

Ex. W8 : Copy of the order dt. 29-11-95 of the Hon'ble High Court in WPMP No. 33077/95 in WP 26835.

Ex. W9 : Affidavit filed by the Respondent in WP No. 26835/95.

Ex. W10 : Application dt. 14-7-92 submitted to RLC complaining about the termination of services of WW1.

Ex. W11 : Minutes of discussions held on 28-10-93 before RLC.

Ex. W12 : Conciliation Failure Report dt. 6-6-94 submitted to the Govt. of India New Delhi by ALC (Central) Hyd.

Ex. W13 : Proceedings dt. 30-6-92 regarding the authorisation of casual labour.

Documents marked for the Respondent-Management

Ex. M1 : Xerox copy of the Proceedings dt. 28-4-93 enhancing the loading/unloading charges from Rs. 18/- to Rs. 22/- per 100 quintal.

Ex. M2 : Sample Bill submitted by Vazcer Patel the leader of Hamalies for the month of Jan. 1990 submitted to MW1 for forwarding to Head Office for perusing the same.

Ex. M3 : -do-

Ex. M4 : Copy of the Pay order authorising the Stn Supdt. to pay the amounts mentioned therein to Sowkar Hamalies.

Ex. M5 : Notification dt. 7-12-89 issued by the Govt. of India notifying certain Rly. Stns. for application of Minimum Wages Act to pay minimum wages to Hamalies.

Ex. M6 : Xerox copy of the Memo sent by MW1 to Chief Comml. Supdt. not to allow outsiders the parcels and luggages.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1328:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे, राजकोट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, -1, राजकोट के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/72/97-आई.आर.(डी.)/बी.-1]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April, 1997

S.O. 1328:—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, -I, Rajkot as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway Rajkot and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-4-97.

[No. L-41011/72/97-IR(D)/B.-I.]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

Before Shri H. S. Mehta
Industrial Tribunal (I), Rajkot
Ref. (ITC) No. 53/95
Adjudication Between

Divisional Railway Manager,
Western Railway, Kothi compound
Rajkot

And

Zonal Secretary
Paschim Railway Karamchari Parishad
209-E, Sarvottam Nagar
Sabarmati
Ahmedabad.

AWARD

The industrial dispute between the aforesaid parties has been referred to this tribunal u/s 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Central Government, vide Ministry of Labour, New Delhi, order No. L.41011/72/97-IR (D) dt. 28-8-95. The dispute relates to the demand which reads as under.

“Whether the claim of P.R.K.P. for seniority to Shri Mohanlal and 8 other workmen in the diesel-shed, Abu Road from 1978 as initiated in the demand notice at annex. A is legal and justified? If so, to what relief the workmen are entitled”.

2. In this case, notice to file the statement of claim is served to the union, however, the union has not filed any statement of claim so far. It seems from the record that the matter has been adjourned from time to time but the union has not filed any statement of claim so far. It seems that the union has no interest to proceed with this matter. In my opinion, this reference should be dismissed for default. I therefore pass order below :

ORDER

Reference is dismissed for want of prosecution.

No order as to cost.

Rajkot, dt. 21-3-97

H. S. MEHTA, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1329:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे, राजकोट के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, -1, राजकोट के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41011/8/93-आई.आर.(डी.)/बी.-1]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April, 1997

S.O. 1329:—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, -I Rajkot as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Railway Rajkot and their workmen, which was received by the Central Government on the 24-4-97.

[No. L-41011/8/93-IR(D)/B.-I.]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

Before Shri H. S. Mehta
Industrial Tribunal (I), Rajkot
Ref (ITC) No. 54/95
Adjudication Between

Divisional Railway Manager,
Western Railway, Kothi compound
Rajkot

And

Zonal Secretary
Paschim Railway Karamchari Parishad
18, Saraswati Nagar, Juna Achid,
Sabarmati
Ahmedabad.

AWARD

The industrial dispute between the aforesaid parties has been referred to this tribunal u/s 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Central Government, vide Ministry of Labour, New Delhi, order No. L- 41011/8/93-IR (D) dt. 28-8-95. The dispute relates to the demand which reads as under.

"Whether the claim of P.R.K.P. for seniority to Shri Batukbhai J, and 12 other workmen in the diesel-shed, NPON (wagon) Shop as initiated in the demand notes at annex. A is legal and justified ? If so, what relief the workmen entitled ?".

2. In this case, notice to file the statement of claim is served to the union, however, the union has not filed any statement of claim so far. It seems from the record that the matter has been adjourned from time to time but the union has not filed any statement of claim so far. The union does not seem to have any interest to proceed with this matter. In my opinion, this reference should be therefore dismissed for default. Hence, I pass the order below :

ORDER

Reference is dismissed for want of prosecution.
No order as to cost.

Rajkot, dt. 29-3-97

H. S. MEHTA, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1330:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार तिरुपती, आर. एम. एस. डिविजन, मद्रास के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/113/92-आई.आर.(डी.यू.)]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April] 1997

S.O. 1330:—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Tirupathi, R.M.S. Division, Madras and their workman, which was received by the Central Government on the 24-4-97.

[No. L-40012/113/92-IR(DU)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMILNADU MADRAS.

Monday, the 30th day of December, 1996

Present :

Thiru S. Thangaraj, B.Sc., L.L.B.,
INDUSTRIAL TRIBUNAL

INDUSTRIAL DISPUTE No. 104 of 1993

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, 1947 between the Workman and the Management of RMS Division, Tirupathi, Madras).

Between

Shri G. B. Singh,
Veena Nursing Home, Madamanur Colony,
Monobolu (S.O.), Gudur R.M.S.

And

The Superintendent,
Tirupathi R.M.S. Division,
Kilpauk, Madras-600010.

Reference : Order No. L-40012/113/92-IR(DU), Ministry of Labour, dated 12-11-93, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday, the 26th day of November, 1996, upon pursuing the claim and counter statement and all other material papers on record, and upon hearing the arguments of Thiru G. Justin, Advocate appearing for the workman and of Thiru R. Karunnakaran, Addl. Standing Govt. Council, appearing for the management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

Government of India, vide their Order No. L-40012/113/92-IR(DU), Ministry of Labour, dated 12-11-93, referred to this Tribunal the following dispute for adjudication.

"Whether the action of the superintendent, R.M.S. Tirupathi Division, Tirupathi in ordering Shri G.B. Singh, Mail Guard to voluntarily retire w.e.f. 1-6-1987 is justified If not, to what relief the workman entitled".

After services of notices, both the petitioner and the respondent appeared before this Tribunal and filed their claim and counter statement respectively.

3. The main averments found in the claim statement are as follows :

The petitioner Shri G.B. Singh was working as Mail Guard under the respondent and he submitted a letter dated 3-3-87 seeking permission to voluntary retirement. By another letter dated 7-3-87 he addressed to the Superinten-

dent, R.M.S. Tirupathi Division, he withdraw the letter seeking permission for voluntary retirement. However, the respondent by an order dated 23-3-87 voluntarily retired him from service w.e.f. 3-3-87. Since he had withdraw the letter dated 3-3-87 the order passed by the respondent voluntarily retiring him from service w.e.f. 3-3-87 on the basis of the said letter is illegal, and against the principles of natural justice. Hence the petitioner may be reinstated with continuity of service and other attendant benefits.

4. The main averments found in the counter filed by the respondent are as follow :

By his letter dated 3-3-87 the petitioner sought permission for voluntary retirement. The question has been considered carefully and he was permitted to retire voluntarily with effect from 3-3-87. After applying for voluntary retirement from service, the Government servant has no right to withdraw the letter with a view to continue in his service. The petitioner has received his retirement benefits. The appointing Authority never compelled the petitioner to receive such amounts. If the petitioner was really interested to have reinstatement, he should not have received the payment which he was entitled to receive on the eve of his retirement. The petitioner has approached the Industrial Tribunal after receiving all the benefits of voluntary retirement that too after lapse of seven years. The petitioner is trying to derive some monetary benefit without physically rendering any service by taking shelter under the canons of law. The prayer of the petitioner is unjustified and award may be passed confirming the voluntary retirement.

5. The petitioner was examined as a witness on his side. Exs. W-1 to W-6 have been filed on his side. No witness was examined on the side of the respondent. Exs. M.1 to M.3 have been marked on the side of the respondent.

6. The only point for our consideration is : Whether the action of the Superintendent of R.M.S. Tirupathi Division, Tirupathi, in ordering Shri G.B. Singh, Mail Guard to voluntarily retire w.e.f. 1-6-87 is justified ? If not to what relief the workman entitled.

7. The petitioner Shri G.B. Singh was a Mail Guard in the RMS Tirupathi Division, Tirupathi. On 3-3-87, he has sent Ex. W-1 letter for voluntary retirement from service. It seems from the said letter that he was appointed in the respondent division on 14-12-65. It is only after 22 years of service, he had sent Ex. W-1 letter for voluntary retirement. The petitioner did not say that without knowing the consequences he had sent Ex. W-1 letter. It was not the case of the petitioner that under some compulsion or misrepresentation he had to send such letter. Even from his statement it is clear that Ex. W-1 letter was a voluntary one. However, on 7-3-87 he thought fit not to go on voluntary retirement and thereafter sent Ex. W-2 letter to permit him to continue in service. Respondent passed Ex. W-3 orders for voluntary retirement as per his letter Ex. W-1. The petitioner has reviewed his own decision of retiring from

service and his request to continue in service was not considered as the respondent management has acted on the letter Ex.W-1 voluntarily written by the petitioner. All the benefits have been received by the petitioner in consequent to his voluntary retirement order. Ex. M.1 to M.3 clearly show that the petitioner has received all the pensionary benefits on account his voluntary retirement from service. If the petitioner was really interested in continuing the service he ought not to have received such benefits. The reasons adduced on the side of the respondent that the petitioner having received pensinary benefits on account of his voluntary retirement had come forward to derive more benefits under the cannons of law cannot be brushed aside easily. When once the petitioner has accepted the voluntary retirement. If he had changed the earlier option for voluntary retirement and continue to be in service he would not have received the retirement benefits. On the contrary after receiving the voluntary retirement and thereafter making a claim under the canons of law is nothing but a calculative attempt on the part of the petitioner to gain double benefits.

8. The petitioner has not raised an industrial dispute immediately after the acceptance of his request for voluntary retirement. It is only after the receipt of his voluntary retirement benefits he had gone before the Administrative Tribunal and had voluntarily not pressed the petition filed by him and thereafter he had raised this Industrial disputes. So, there is nearly 7 years delay in raising the Industrial dispute. It was argued on the side of the respondent that with a view to claim more benefits the petitioner has adopted these methods for receiving salary without doing any work. This argument of the respondent cannot be brushed aside easily. Therefore, there is no valid reason to accept the claim of the petitioner. On contrary if such claims are accepted it will totally prejudice the respondent.

9. Further in Sub Divisional Inspector of Posts, Vaikam & Ors. Vs. Theyyam Joseph (1996 II LLJ P. 230) Apex Court held that, 'one of the duties of the State is to provide telecommunication services to the general public and an amenity and so is one of essential part of the sovereign functions of the State as a Sovereign State and therefore Post Office is not an industry'. The R.M.S. is one of the units of the Indian Posts and Telegraph Service. It was argued on the side of the petitioner in Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa (1978 I I.L.J P. 349) the Supreme Court held that Post and Telegraph service is an industry. However, in the recent judgement stated supra our Supreme Court had gone into the question and has decided that the Post Office is not an industry. Article 141 of the Constitution of India says :

"The Law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts within the territory of India."

Therefore, the recent decision of our Supreme Court reported in 1996 II LLJ P. 230 is binding on this Tribunal. On the basis of the said decision it has to be held that since Post and Telegraph Department is not an industry, the in-

dustrial dispute is not maintainable.

From the foregoing discussion, it is clear that the petitioner is not entitled for any of the claims as prayed for.

10. In the result, award is passed dismissing the claim of the petitioner. No costs.

Dated, this the 30th day of December, 1996.

S. THANGARAJ, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For Petitioner :

W. W. 1 : Thiru G. Balaram Singh.

For Management : None.

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner :

Ex. W-1/3-3-1987 : Letter given by petitioner for voluntary retirement (xerox copy).

W-2/7-3-87 : letter given by petitioner withdrawing Ex. W-1 (xerox copy).

W-3/23-3-87 : Retirement order issued by respondent (xerox copy).

W-4/27-5-87 : Representation given by petitioner to the respondent (xerox copy).

W-5/20-8-90 : Original Application No. 375/90 filed by petitioner in CAT, Madras Bench (xerox copy).

W-6/23-4-91 : Xerox copy of order of CAT dismissing Ex. O.A. 375/90 (xerox copy).

For Management :

Ex. M.1/24-2-88 : Xerox copy of Order of DAP (A/cs) sanctioning commutation of value of DCRO and sanction of pension of Rs. 250/-.

M-2/-02-88 : Sanction of Rs. 1031/- being the 10% of DCRG of DA(P), Hyderabad (xerox copy).

M-3/24-2-88 : Sanction of PPO by DAP, Hyderabad (xerox copy).

Sd/- S.T.
I T.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1997

का.आ. 1331:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जोधपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/151/91-आई.आर.(बी. 3)/बी.-I.]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th April, 1997

S.O. 1331:—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Thar Anchalik Gramin and their workman, which was received by the Central Government on the 24-4-97.

[No. L-12012/151/91-IR(B-3)/B.-I.]

K.V.B UNNY, Desk Officer

अनुबंध

श्रम न्यायालय, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री महेंद्र कुमार जैन, आर. एच. जे. एस.

औ. विवाद संख्या :— 2/1991

श्री पृथ्वीसिंह जरिये सचिव, आल इण्डिया ग्रामीण बैंक वर्क्स आरगेनाइजेशन सेंटरल ऑफिस बी. 32, न्यू लाईट कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। ...प्रार्थी

बनाम

अध्यक्ष थार आंचलिक ग्रामीण बैंक ब-54 शास्त्री नगर, जोधपुर।अप्रार्थी

उपस्थिति :—

(1) प्रार्थी की तरफ से श्री डी. के. चौहान प्रतिनिधि उप.

(2) अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

अधिनियम

दिनांक 6-2-1997

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी द्वारा निम्न विवाद वास्ते अधिनियम जरिये आदेश क्रमांक एल.12012/151/91-आई. आर.(बी.-3) दिनांक 3-7-1991 प्रेषित किया गया है :—

Whether the action of the management of Thar Anchalik Gramin Bank in terminating the services of Shri Prithivi Singh, Messenger, Lordia Branch, w.e.f. 3-2-1985 was justified?

2. Whether the action of the bank management in denying wages to the workman during the period from 3-2-85 to 20-5-85, having re-employed the workman w.e.f. 21-5-85 was justified?

If answer to both is in the negative, to what relief the workman is entitled to?"

2. उक्त रेफरेन्स इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 16-8-91 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस प्रकरण में दिनांक 21-5-1996 को प्रार्थी को माँग-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाकर 23-7-1996 तारीख पेशी नियत की गई, लेकिन प्रार्थी की तरफ से दिनांक 23-7-1996 व उसके पश्चात नियत तारीख पेशी 17-9-1996, 19-11-1996, 16-1-1997 व आज दिनांक 6-2-1997 को माँग-पत्र के समर्थन में

शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रार्थी को दिनांक 16-1-1997 को माँग-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया था। इस तरह श्रमिक ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी माँग-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आज प्रार्थी के प्रतिनिधि ने प्रार्थी की तरफ से हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया तथा स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से यही प्रकट होता है कि प्रार्थी इस विवाद को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी नियोजक के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में नोटिस्युट एवार्ड पारित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

3. परिणामस्वरूप इस प्रकरण में "कोई विवाद नहीं अधिनिर्णय" (नोटिस्युट एवार्ड) पारित किया जाता है।

4. इस अधिनिर्णय को वास्ते सूचना एवं प्रकाशन हेतु भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जाये।

5. यह अधिनिर्णय आज दिनांक 6-2-1997 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

महेन्द्र कुमार जैन, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1997

का. आ. 1332:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मद्रास टैलीफोन्स के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-4-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/185/91-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/186/91-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/29/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/27/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/256/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/181/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/131/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/228/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/212/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/34/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/113/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/148/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/135/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/156/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/226/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/227/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/229/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/232/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/163/93-आई.आर. (डी.यू.)]

[सं. एल-40012/73/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/211/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/22/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/226/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/162/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/113/93-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40011/9/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/158/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/32/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/36/92-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40011/33/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40011/13/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40011/12/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/91/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/110/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/230/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/228/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/243/94-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/29/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/127/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/90/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/137/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/124/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/135/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/168/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/169/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/170/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/171/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/172/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/173/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/176/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/177/95-आई.आर. (डी.यू.)]
[सं. एल-40012/213/94-आई.आर. (डी.यू.)]

के. वी. बी. उन्नी, डैस्क ऑफिसर

New Delhi, the 25th April, 1997

S.O. 1332:—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Madras Telephones and their workman, which was received by the Central Government on the 25/4/97.

[No. L-40012/185/91-IR(DU)]
 [No. L-40012/186/91-IR(DU)]
 [No. L-40012/29/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/27/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/256/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/181/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/231/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/228/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/212/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/34/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/35/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/148/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/135/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/156/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/226/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/227/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/229/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/232/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/163/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/73/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/211/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/22/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/226/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/162/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/113/93-IR(DU)]
 [No. L-40012/9/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/158/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/32/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/36/92-IR(DU)]
 [No. L-40012/33/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/13/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/12/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/91/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/110/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/230/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/228/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/243/94-IR(DU)]
 [No. L-40012/29/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/127/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/90/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/137/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/124/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/135/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/168/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/169/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/170/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/171/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/172/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/173/95-IR(DU)]

[No. L-40012/176/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/177/95-IR(DU)]
 [No. L-40012/213/94-IR(DU)]
 K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

MADRAS

Monday, the 30th day of December, 1996

Present :

THIRU S. THANGARAJ, B.Sc., LL.B.,

Industrial Tribunal

INDUSTRIAL DISPUTE NOS. 53/1992, 59/1992, 12/1993, 13/1993 I.D. 6/94, I.D. 145/94, I.D. 146/94, I.D. 17/93, I.D. 161/94, I.D. 162/94, I.D. 163/94, I.D. 199/94, I.D. 200/94, I.D. 212/94, I.D. 213/94, I.D. 214/94, I.D. 215/94, I.D. 216/94, I.D. 1/95, I.D. 3/95, I.D. 8/95, I.D. 9/95, I.D. 15/95, I.D. 28/95, I.D. 29/95, I.D. 45/95, I.D. 48/95, I.D. 49/95, I.D. 60/95, I.D. 62/95, I.D. 66/95, I.D. 70/95, I.D. 71/95, I.D. 1/96, I.D. 6/96, I.D. 9/96, I.D. 22/96, I.D. 34/96, I.D. 49/96, I.D. 50/96, I.D. 59/96, I.D. 73/96, I.D. 74/96, I.D. 75/96, I.D. 76/96, I.D. 77/96, I.D. 78/96, I.D. 79/96, I.D. 80/96, I.D. 81/96, I.D. 82/96, I.D. 83/96.

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of Postal and Telecom Department)

Between

In I.D. 53/92
 Shri K. Karuna, s/o. Mr. Kannan,
 58, Waltex Road, Jakkapuram,
 Madras-10

and

The Chief General Manager,
 Madras Telephones,
 78, Purasawalkam High Road,
 Madras-104.

Reference : Order No. L-40012/185/91-IR (DU). Ministry of Labour, dt. 19-6-92, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 59/92

Shri D. Muthukrishnan, 23, M.M. Garden, Vysarpadi,
 Madras-600 039.

and

The Chief General Manager, Madras Telephones,
 No. 78, Purasawalkam High Road, Madras-600 010.

References : Order No. L-40012/186/91-IR (DU) Ministry of Labour, dt. 25-6-92, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 12/93

Shri A. Thiagarajan, C/o. Paul Raj Nadar,
146, G. R. Road, Theni, Permakulam Taluk,
Madurai-31. 625 031.

and

The Supdt. of Post Offices, Madurai,
Moffusil Division, Madurai-625 002.

Reference : Order No. L-40012/29/92-IR (DU). Ministry
of Labour, dt. 18-1-93, Govt. of India, New
Delhi.

In I.D. 13/93

Shri P. Rajamani, S/o. Shri Ponnumani,
EDDA Hirathur, Manali Veedu-625 164.

and

The Sub-Divisional Inspector (Postal),
Kulithurai Sub-division, Kulithurai dt-629 163.

Reference : Order No. L-40012/27/92-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 19-1-93, Govt. of India, New
Delhi.

In I.D. No. 17/93

Shri P. Muralidoss, No. 37-A, Lalpet Street,
Chidambaram-608001.

and

The Divisional Engineer, Office of Telecom,
District Manager, Cuddalore-607001.

Reference : Order No. L-40012/256/92-IR (DU). Ministry
of Labour, dt. 20-1-93, Govt. of India, New
Delhi.

In I.D. No. 6/1994

Shri D. Devanesan, Extra Departmental Delivery Agent,
Ranumamamoodu, Branch Office,
Kanyakumari Dt. 629 001.

and

The Senior Superintendent of Post Offices,
Kanyakumari Division, Nagercoil,
Tamil Nadu-629 001.

Reference : Order No. L-40012/181/92-IR (DU). Ministry
of Labour, dt. 21-1-94, Govt. of India, New
Delhi.

In I.D. No. 145/94

Thiru L. Vendatasubramanian, No. 10, B. Agraharam,
Kamabarasembettai, Trichy-101.

AND

The Sr. Supdt. RMS (T) Division,
Trichirapalli.

Reference : Order No. L-40012/231/92-IR (DU). Ministry
of Labour, dt. 13-5-94/10-9-94, Govt. of India,
New Delhi.

In I. D. No. 146/94

Shri M. Muthu, C/o. M. Murugaiah, Circle
Organising Secretary, N. F. T. E-E4 Cross
Bar Exchange, Rajapalayam-626117.

and

The Telecom District Engineer, Virudhunagar-626001.

Reference : Order No. L-40012/228/92-IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 13-5-94/10-9-94, Govt. of India, New
Delhi

In I. D. No. 161/94

Shri K. Ravindran, S/o. Karunanidhi, Ex-
Branch Post Master, Veivillakku Branch Office,
Karuvapuram S. O., Vedaranyam Taluk-614808

and

Supdt. of Post Offices, Pattukottai Divn.,
Pattukottai-614601.

Reference : Order No. L-40012/212/93-IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 13-7-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 162/94

Shri M. Michael Raj, 7/139, Railway Station Road,
Mettur Post-627 436.

and

The Sr. Supdt. of Post Offices, Kovilpatti-701.

Reference : Order No. L-40012/34/93- (DU), Ministry of
Labour dt. 13-7-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 163/94

Shri P. Pillayar Murugaiah, ED Branch Post Master,
Sangarettikottai P. O. Nellikottai Tak., Anna Dt.

and

The Sr. Supdt. of Post Offices, Dindigul Divn.,
Dindigul-624 007.

Reference : Order No. L-40012/35/93/IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 13-7-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 199/94

Ms. Seeniammal, D/o. Mookan, Kattunaichan St.,
Vasudevanallur-627 758.

and

The Supdt. of Post Office, Kovilpatti Divn.,
Kovilpatti-627 701.

Reference : Order No. L-40012/148/93-IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 16-11-94, Govt. of India, New
Delhi.

In I. D. 200/94

Shri R. Thirunavukkarase, 40, Sivaraja Puram,
1st Street, Pullianthope, Madras-12.

and

The General Manager, Telecommunication, Vavoo
Mansion, Rajaji Salai, Madras-600 001.

Reference : Order No. L-40012/135/93-IR(DU), Ministry of
Labour dt. 16/29-11-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 212/94

Thiru P. V. Sukumarakrishnan, No. 49, Corporation Small
Line, Shivarao Road, Pattalam, Madras-12.

and

The Sr. Manager, Mail Motor Service,
D/o. Posts, Madras 600 006.

Reference : Order No. L-40012/156/94-IR (DU), Ministry
of Labour dt 16-12-94, Govt. of India, New
Delhi.

In I. D. 213/94

Shri V. Nagarajan, C/o. M. Murugaiah, Circle Organising
Secretary, NFTE E4, Cross Bar Exchange, Rajapalayam.

and

The Telecom District Engineer, Nagercoil-629 001.

Reference : Order No. L-40012/226/92-IR(DU), Ministry of
Labour, dt. 19-5-94 Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 214/94

Shri P. Udayakumar, C/o. M. Murugaiah, Circle Organising
Secretary, NFTE E4 (T. N.) Cross Bar Exchange,
Rajapalayam.

and

The Telecom District Engineer, Virudhunagar-626 601.

Reference : Order No. L-40012/227/92-IR(DU), Ministry of
Labour, dt. 19-5-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 215/94

Shri M. Kannan, C/o. M. Murugaiah, Circle Organising Sec-
retary, NFTE E4 (TN) Cross Bar Exchange, Rajapalayam.

and

The Telecom District Engineer, Virudhunagar-626 001.

Reference : Order No. L-40012/229/92-IR(DU), Ministry of
Labour, dt. 19-5-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 216/94

Shri S. Dharmaraj, C/o. M. Murugaiah, Circle Organising
Secretary, NFTE E-4, Cross Bar Exchange, Rajapalayam.

and

The Telcom District Engineer, Virudhunagar.

Reference : Order No. L-40012/232/92-IR(DU), Ministry of
Labour, dt. 19-5-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. No. 1/95

Shri Stanley Jones, Kotthapakkam Village,
Vadagathapatty Post (via), Madanoor, N. A. Dist.-635 804.

and

1. Sr. Supdt. of Post Offices, Dept. of Posts,
Tirupattur Divn., Tirupattur 635601 N. A. Dist.

2. The Sub-Divisional Inspector, Dept. of Posts,
Vaniyambadi Sub-division, Vaniyambadi-635 601.

Reference : Order No. L-40012/163/93-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 28-12-94, Govt. of India, New
Delhi.

In I. D. 3/95

Shri K. Vasudevan, S/o. Parameswaran, No. 6, Extn. 4,
Thiruvalluvar Nagar, Kottur, Madras-85.

and

The Chief Supdt., Central Telegraph Office,

II Line Beach, Madras-1.

Reference : Order No. L-40012/73/93-IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 22-11-94, Govt. of India, New Delhi.

I. D. 8/95

Shri. N. Ramesh, S/o. Nallana Naidu, EDDA,
Kuppinaickanpatty, Kamatchipuram S.O.-626 530.

and

Sr. Supdt. of Post Offices, Mofussil Divn., Madurai-625002.

Reference : Order NO. L-40012/211/93-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 20-1-95, Govt. of India, New
Delhi.

In I. D. 15/95

Shri D. Sellamuthu, S/o. Duraisamy, Silliampatty B. O.,
Attur Taluk, Salem-636 107.

and

Director Sr. Supdt. of Post Office, Salem East Divn.,
Salem 636 001.

Reference : Order No. L-40012/22/94-IR (DU), Ministry of
Labour dt. 22/24-2-95, Govt. of India, New Delhi.

I. D. 28/95

Shri G. Venkatesan, No. 2/81, Karaikkan Street,
Nerkundram, Madras-600 107.

and

The Divisional Engineer, Madras Telephones, Kellys I No.
22, Kellys Road, Madras-600 017.

Reference : Order No. L-40012/22/94-dt. 22-6-95, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 9/95

Sh. V. Sarvesan, S/o. Veeraraghavan, Periyakurichi Village, Tirupattur Bazar, Pin 635 602.

and

The Supdt., RMS 'M' Divn., D/o. Posts, Madras-3.

Reference : Order No. L-40012/162/93-IR-(DU), Ministry of Labour, dt. 28-12-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. No. 29/95

Shri G. Rajendran, No. 38, Kutty Street, Nungambakkam, Madras-38. 600 034.

and

The Divisional Engineer, Madras Telephones, Kellys I. No. 22, Kellys Road, Madras-10.

Reference : Order No. L-40012/113/93-IR-(DU), Ministry of Labour dt. 22-6-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 45/95

Divisional Secretary, All India Postal Employees Class III ED, Nagapattinam, Q M Dist. 611 001.

and

Post Master General, Tiruchirapalli Region, Tiruchirapalli 620 001.
Superintendent of Post Office, Nagapattinam 611 001.

Reference : Order No. L-40011/9/94-IR-(DU), Ministry of Labour dt. 20-7-94/4-8-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 48/95

Shri N. Kumaravel, 1/65, Sirukundran Post, Sembakkam, (via) Chengalpattu Dt. 603 108.

and

General Manager, Madras Telephones, 17, P. H. Road, Madras-7.

Reference : Order No. L-40012/158/94-IR-(DU), Ministry of Labour of dt. 4-8-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 49/95

Shri R. Vedakrishnan, No. 57, 2nd Street, Natarajapuram, Namakkal 637 001.

and

The Supdt. of Post Office, Namakkal Divn., Namakkal. 637 001.

Reference : Order No. L-40012/32/94-IR-(DU), Ministry of Labour dt. 4-8-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 60/95

Shri C. T. Jayaraman, MV Electrician, No. 1/153, Balaganesh Nagar, Red Hills, Madras-52.

and

Senior Managar, P & T, Motor Service, Madras-6.

Reference : Order No. L-40012/36/92-IR-(DU), dt. 5-9-95, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 62/95

Shri P. Mohankumar, S/o. Pachaiyappan, Puilalpatty (Kuttuvallaval) Macherry Post, Salem Dt. 2.

and

1. Sub-Divisional Inspector, (Postal), Mettur Dam Sub-division, Mettur Dam-636 401.
2. The Supdt. of Post Offices, Salem District, Salem-636005.

Reference : Order No. L-40012/13/94-Ministry of Labour, dt. 4-9-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 66/95

1. The Divisional Secretary, AITEU (Cl. III), & EDAs Myladuthurai 609 001.
2. The Divisional Secretary, AITEU Postman and Cl. IV Myladuthurai 609 001.
3. The Divisional Secretary, NUTE (Cl. II) & EDA Myladuthurai 609 001.
4. The Divisional Secretary, BPEU, Cl. III, Myladuthurai, 609 001.
5. The Divisional Secretary BPEU (Cl. IV) & Postman, Myladuthurai 609 001.

and

The Post Master General, Central Regional, Trichirapalli-620001.

2. The Supdt. of Post Offices, Myladuthurai-609 001.

Reference : Order No. L-40012 /13/94-IR-(DU), Ministry of Labour, dt. 5-9-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 70/95

The Divisional Secretary, All India Postal Employees Union, Nagapattinam, QM Dist. T. Nadu-611 001.

and

1. The Post Master General, Central Region, Trichirapalli-620 001.
2. Supdt. of Post Offices, Nagapattinam-611 001.

Reference : Order No. L-40011/12/94-IR-(DU), Ministry of Labour dt. 20-7-94, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 71/95

Shri R. Pillai Perumal, Ex. Branch Post Master,
Seethaprappanallur B. O. Gandhinagar S. O. 627 008.
and

The Sr. Supdt. of Post Offices, Tirunelveli Divn.,
Tirunelveli. 627 002.

Reference : Order No. L-40012/91-95-IR(DU), Ministry of
Labour, dt. 27-10-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 1/1996

Shri S. Sundarajan, S/o. No. 199, 'B' Block, West Cemetery
Road, Old Washermanpet, Madras-21.

and

The Assistant Chief Supdt. Central Telegraph Office.
Madras-600014.

Reference : Order No. L-40012/110/94-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 27-12-95, Govt. of India, New
Delhi.

In I. D. 6/1996.

Shri A. Meera Mohideen, S/o. Sh. Abdul Rehman,
Purathukudi, Trichy Dt.

AND

The Divisional Engineer (Telegraph) Coaxial Maintenance,
CTC Compound, Madras-2

Reference Order No. L-40012/230/94-IR(DU), Ministry of
Labour, Dt. 27-12-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 9/1996.

Shri M. Murugan, S/o. 1B, Nachi Nadar Street,
Virudhunagar, 626001.

and

The Director of Postal Services, O/o. Post Master General,
Southren Region, Madurai-625002.

Reference : Order No. L-40012/228/94-IR (DU). Ministry
of Labour, dt. 27/28-12-95, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 22/96

Shri S. G. Elumalai, 2/42, Bajanai Koil Street, Sehuvalai,
North Arcot Ambedkar Dt. 632 104.

and

Sr. Supdt. of Post Offices, Vellore Division,
Vellore-632 001.

2. Asstt. Supdt. of Post Offices, Vellore East Sub-Division,
Vellore 632 001.

Reference: Order No. L-40012/243/94-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 26-2-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 34/96

Smt. A. Dhanalakshmi, Kallakurichi Taluk, Chinnasalem-
606 201.

and

Sr. Supdt. of Post Offices, Virdhachalam, Divn.,
Vridhachalam-606601.

Reference: Order No. L-40012/29/95-IR (DU), Ministry of
Labour, dt. 27-3-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 49/96

Shri V. Marudhavinayagam, C/o N.K. Kasi, No. 50, Land
Street, North Attur-628 151.

and

Sr. Supdt. of Post Offices, Tuticorin Divn.,
Tuticorin-628 008.

Reference : Order No. L-40012/127/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-6-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 50/96

Shri M. Thangaraj, S/o Madasamy, Karadikulam B.O.,
Kalugumalai-627 752.

and

The Sr. Supdt. of Post Offices, Kovilpatti Divn., Kovilpatti-
627 702.

Reference : Order No. L-40012/90/95-IR (DU), Ministry of
Labour dt. 27-6-96, Govt. of India, New Delhi.

I. D. 59/96

Shri K. Ramaswami, Sundamettupudur, Konganapuram,
637 102. Salem Dt.

Supdt. of Post. Offices, Namakkal Division Namakkal-
637 002.

and

Reference : Order No. L-40012/137/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-6-96, Govt. of India, New Delhi.

I.D. 73/96

Shri A. Raju, Kanjanaickanpatti, B.O. a/w Pannapatti,
S/o 636 005.

and

Asstt. Supdt. of Post Offices, Suramangalam Sub-division,
Salem West Postal Division, Salem 636 004.

2. Director of Postal Services, Western Region, O/o. Post
Master General, Coimbatore, T. Nadu.

3. Supdt. of Post Offices, Salem West Division,
Salem 636 004.

4. The Director General of Post, D.O. Post, Ministry of
Communication, New Delhi 110 001.

Reference : Order No. L-40012/124/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 26-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 74/96

Shri N. Kodandan, M. Perumalpalayam B.O.
Sajjanchavadi, S.O. Salem Dt.-636 111.

and

Sr. Supdt. of Post Offices, Salem East Division,
Salem-636 001.

The Director of Postal Services, Western Region,
Coimbatore-641 002.

Post Master General, Western Region, Coimbatore,
641 002.

Reference : Order No. L-40012/135/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 26-8-96, Govt. of India, New Delhi

In I. D. 75/96

Shri S. Bhaskaran, M. Sevaiyan, Singalandi,
Thriuthuraipoondi, P.O. & Th. 614 713.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference : Order No. L-40012/168/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 76/96.

Shri S. Dravidamani, S/o Sambandan Pillai, 26C/2,
Uppukula Street, Thiruthuraipoondi, P.O.-614 713.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference : Order No. L-40012/169/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 77/96

Shri. C. Murugaiyan, S/o. Pichan, Agarusathangudi,
Mangudi P.O. Thiruvapur Tak. T. Nadu-610 106.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference : Order No. L-40012/170/95-IR (DU), dt. 27-8-96,
Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 78/96

Shri R. Ghanasekaran, S/o. Ramaiyan, Arivan Theru,
Thiruthuraipoondi P.O. & Tk., Pin-614 713.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference : Order No. L-40012/171/95-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 79/96

Shri K. Sreenivasan, S/o Kannusamy, Singalandi,
Thiruthuraipoondi, PO. & Tk-614 713.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur-613 001.

Reference: Order No. L-40012/172/95-IR (DU), Ministry
of Labour, dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 80/96

Shri V. Rayar, S/o Sh. Velu, Sikar P.O. Thaplampuliyur
(via), Tiruvarur Tk 610 106. T. Naidu

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur-613 001.

Reference : Order No. L-40012/173/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I.D. 81/96

Shri N Arivalagan, S/o. Nagarajan, Kodikkal St., Pamke
Road, Thiruvapur PO & Tk.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference: Order No. L-40012/176/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 82/96

Shri K. Natarajan, S/o Kuppan, Singalandi, Thiruthuraipoon
PO & Tk, Pin 614 713.

and

The General Manager, Dept. of Telecommunications
Thanjavur 613 001.

Reference : Order No. L-40012/177/95-IR (DU), Ministry
of Labour dt. 27-8-96, Govt. of India, New Delhi.

In I. D. 83/96

Shri. S. Rundaresan, EDDA, II, Edaikodu Sub office,
Kanyakumari Dt. T. Nadu

and

The Sr. Supdt. of Post Offices, Kanyakumari Division
Nagercoil, T. Nadu.

Reference : Order No. L-40012/213/A/94-IR (DU),
Ministry of Labour dt. 26-8-96, Govt. of India, New Delhi.

This disputes coming on for final hearing on Monday,
the 26th day of November, 1996, upon perusing the refer-
ences, and all other papers on record, and upon hearing the
arguments of Tvl. D. Hariparanthaman, A.M. Krishnamurthy,
S. James, Ms. Jothivani, R. Ganesan, G. Devesan,
R. Malaisamy, S. Elango, G. Chamkiraj, Justin, P. Selvaraj,
P.V. S. Giridhar, and U. Padmanabhan for petitioners and
Tvl. R. Karunakaran, S. Thiagarajan, C K. Vishnupriya,

K. Kumar, T. K. Rajeswaran, Ravikumar, and S. Seshadri Advocates appearing for the Management, and these disputes having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

On service of notices both petitioners and respondent appeared before this Tribunal.

In all these references, the following common issue has to be adjudicated.

“Whether the action of the management of Post & Telecom Department, in the services of their workman is justified. If not, what relief the concerned workman concerned is entitled to?”

3. All these Industrial Disputes have been raised under different references of the Government of India, on different dates, by the employees of the Postal and Telecom Departments are not industries and therefore the industrial disputes are not maintainable in the Industrial Tribunal. They based reliance on the recent ruling of the Apex Court of India pronounced on 2-2-96 in SUB-DIVISIONAL INSPECTOR OF POST, VAIKAM & ORS. Vs. THEYYAM JOSEPH (1996 II LLJ P 230). The Postal Department of Telecom Departments were within the definition of Industry under Sec. 2(i) of the Industrial Disputes Act, 1947. However, the above recent decision of our Supreme Court has held that Postal and Telecommunications departments are not “industry” within the meaning of the said Act. Now the question arises regarding the jurisdiction of this Tribunal. Both the parties have argued elaborately on this question.

4. The major point for our consideration is : Whether this Tribunal has jurisdiction to decide these Industrial disputes referred to?

5. The Point: In Sub-Divisional Inspector of Posts Vaikam Vs. Theyyam Joseph (1996 II LLJ P 230) at page 231, 232 and 233, Apex Court held ;

“Having regard to the contentions, the question arise whether the appellant is an industry? India as a sovereign, socialist, secular democratic, republic has to establish an egalitarian social order under rule of law. The welfare measures under partake the character of sovereign functions and the traditional duty to maintain law and order is no longer the concept of the State. Directive principles of State Policy enjoin on the State diverse duties under part IV of the Constitution and the performance of the duties are constitutional functions. One of the duties is of the State to provide telecommunication service to the general public as an amenity, and so is one essential part of the sovereign functions of the State as a welfare state. It is not, therefore, an industry.”

It would thus be seen that the method of recruitment, the conditions of service, the scale of pay, and the conduct of Rules regulating the service conditions of ED Agents are governed by the statutory regulation. It is

now settled law of this Court that these employees are civil servants regulated by these conduct rules.

Therefore, by necessary implication they do not belong to the category of workmen attracting the provisions of the Act. The approach adopted in the Tribunal, therefore, is clearly illegal. The Tribunal was wholly wrong in directing the appellant to terminate the services in accordance with the provisions of the Act.”

From the above decision it is clear that the Post and Telecommunications Departments are doing sovereign functions of the State and therefore they are not “industry”.

6. The main objections raised by the petitioners, the employees of these departments are as follows:

Section 2(n) (iii) of the I.D. Act, deals with Public Utility Service. It includes “any postal, telegraph or telephone service”. The employees of such services those who fall under the definition of “workman” within the meaning of Sec.2(s) of the I.D. Act, are entitled to invoke the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. Further Sec. 2(s) of the I.D. Act, which defines the “Workman” does not exclude the employees of the Postal, Telegraph and telephone service. Section 9A of the I.D. Act, which deals with notice of change is exempted for workman covered by CCS Rules. For other workmen the jurisdictions of the Industrial Disputes Act, are applicable.

7. The Supreme Court in BANGALORE WATER SUPPLY & SEWERAGE BOARD Vs. A RAJAPPA & ORS (1978 I LLJ P 349) at page 375 says :

“Although we are not concerned in this case with those categories of employees who particularly come under departments charged with responsibility for essential constitutional functions of Government, it is appropriate to state that if there are industrial units severable from the essential functions and possess an entity of their own it may be plausible to hold that the employee of those units are workmen and those undertaking are industries. A blanket exclusion of every one of the host of employees engaged by Government in departments falling under general rubrics like justice, defence, taxation, legislature, may not necessarily be thrown out of the umbrella of the Act. We say no more except to observe that closer exploration, not summary rejection is necessary.”

Further in page no. 405, it was held :

“(a) Where a complex of activities, some of which qualify for exertion, others not involves employees on the total undertaking, some of whom, are not ‘workmen’ as in the University of Delhi case or some departments are not productive of goods and services if isolated even then the predominant nature of the services and the integrated nature of the departments as explained in the Corporation of Nagpur, will be the true test. The whole undertaking will be “industry” although those who are not ‘workmen’ may not benefit by the Status.

- (b) Notwithstanding the previous clauses, sovereign functions, strictly understood, alone qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by Government or statutory bodies.
- (c) Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within S.2(J).
- (d) Constitutional and competently enacted legislative Provisions may well remove from the scope of the Act."

Following the decisions, the various High Courts held that the Postal Telegraph and Telephone service is an industry. In BHASKARAN vs. SUB-DIVISIONAL OFFICER (1982 II LLJ P 248) the Kerala High Court held that "Postal and Telegraph Department is an industry." In TAPAN KUMAR JANA Vs. CALCUTTA TELEPHONES AND ORS. (1981 II LLJ p 382) the Calcutta High Court held that the "Telephone Department is an industry." In K.R.B. KAIMAL AND ANR. Vs. DIRECTOR OF POSTAL SERVICES, TRIVANDRUM (1979 I LLJ p 176) High Court of Kerala held that the "Postal Department is an industry."

8. It was further argued on the side of the petitioner that in Padmavalli's case, full bench of the Central Administrative Tribunal in Vol. II Page 334 (copy of judgement not submitted for perusal), that telephone department is an industry and the workmen concerned can come before the Industrial Tribunal.

9. In Recommendation No. 119 of the International Labour Organisation reads as follows :

"A worker who feels that his employment has been unjustifiably terminated should be entitled, unless the matter has been satisfactorily determined through such procedures within the undertaking, establishment of service, as may exist or be established consistent with this Recommendation, to appeal, within a reasonable time, against the termination with the assistance, where the worker so requests, of a person representing him to a body established under a collective agreement or to a neutral body such as a Court, an arbitrator, an arbitration committee or a similar body."

Section 11A of the I.D. Act, 1947 came into effect on 15-12-71 and the power given to the Labour Courts and Industrial Tribunals under Sec. 11-A to modify the punishments if necessary is not given to the Administrative Tribunals and if the departments of Postal, Telegraph, and Telephone are excluded from jurisdiction of the Labour Courts and Industrial Tribunals the valuable right of the working class to get justice u/s. 11-a of the I.D. Act may not be available to them. To substantiate this point, the petitioners have invited my attention to a decision of our Apex Court in WORKMEN OF

M/s. FIRESTONE TYRE & RUBBER COMPANY OF INDIA (PVT.) LTD.

10. On behalf of the Post and Telecommunications departments the following objects were taken. Now the Post and Telegraph Department is one and the Telecommunication department is separated from it. The Standing Counsels appearing for these two departments have unanimously argued that the decision of the Supreme Court in SUB-DIVISIONAL INSPECTOR OF POSTS, VAIKKAM Vs. THEYYAM JOSEPH (1996 II LLJ p 230) is binding on this Tribunal and the Tribunal cannot decide the validity of the said decision of the Apex Court of India. To substantiate this point, they preferred a decision of our Supreme Court in AMBICA PRASAD MISHRA Vs. STATE OF UTTAR PRADESH (1980 (3) SCC 719), at page 723 :

"It is wise to remember that fatal flaws silenced by earlier rulings cannot survive after death because a decision does not lose authority merely because it was badly argued, inadequately considered and fallaciously reasoned."

11. In Dr. J. JAYALALITHA Vs. Dr. M. CHANNA REDDY, GOVERNOR OF TAMILNADU (1995 I.L.W.R. 525) at page 531 our High Court held;

"We are disturbed by the fact that the petitioner has after making a reference expressly to the judgement, of the Supreme Court in State of Maharashtra Vs. R. S. Nayak AIR 1982 SC 1249, proceeded to urge in the subsequent paragraphs as a proposition directly contrary to the judgement, of the Supreme Court in the said case. It is certainly not open to any petitioner, however high his or her position be, to canvass the correctness of the judgement of the Supreme Court before this Court and that too in an affidavit."

So, the various arguments advanced by the petitioners regarding the decision reported in 1996 II LLJ p 230 cannot be taken into consideration.

12. It was argued on the side of the petitioners that the decision in BANGALORE WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD Vs. RAJAPPA (1978 I LLJ P 349) was by a larger bench and that decision must be followed. To strengthen this point, the petitioners have submitted two decisions. In UNION OF INDIA Vs. K. SUBRAMANIAN (1976) 3 SCC p 677 at page 681, the Apex Court held;

"But we do not think that the High Court acted correctly in skirting the views expressed by larger benches of this Court in the matter which it had done this. The proper course for a High Court, in such a case, is to try to find out and follow the opinions expressed by larger benches of this Court in preference to those expressed by smaller benches of the Court. That is the practice followed by this Court itself. The practice has now crystallized

into a rule of law declared by this Court. If, however, the High Court was of opinion that the views expressed by larger benches of this Court were not applicable to the facts of the instant case it should have said so giving reasons supporting its point of view."

In THE STATE OF U.P. Vs. RAM CHANDRA TRIVEDHI (AIR 1976 SC 2547) the Supreme Court held ;

"Even in cases where a High Court finds any conflict between the views expressed by larger and smaller benches of this Court, it cannot disregard or skirt the views expressed by the larger benches. The proper course for a High Court in such a case is to try to find out and follow the opinion expressed by larger benches of the Supreme Court in preference to those expressed by smaller benches of the Court which practice, hardened as it has into a rule of law, is followed by the Supreme Court itself."

From these two decisions, it is clear that decision of the larger bench of the Supreme Court has to be followed. However a reading of the judgement reported in 1996 ILLJ P 230 it cannot be said that their Lordships have laid down that decision without considering the earlier decision Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa. Though, in the said decision, their Lordships have not specifically stated the said decision, the recent decision is based on the performance of duties which are Constitutional functions. On that ground, their Lordships have held that the duties of the Postal Department fall under the Sovereign function of the State. Their Lordships further held that the order of the Tribunal holding the employee in that case was a "Workman" was illegal and further held that by necessary implication, the Postal Department workmen do not belong to the category of the workmen attracting the provisions of the Industrial Disputes Act. When it has been held by the Apex Court in unequivocal terms that the employees of the Postal department are not within the meaning, this Tribunal has no further say in the matter but to respectfully follow the Apex Court of India. At this juncture it is not the case of anyone that service of telecommunication department is different from that of the Post & Telegraph department. Formerly, it was one and the same department and what is applicable to Post and Telegraph department is equally applicable to the Telecommunications department also.

13. In Smt. KAUSALYA DEVI BOGRA & ORS. Vs. LAND ACQUISITION OFFICER, AURANGABAD (1984 (2) SCC 324) at page 332 & 333.

"The direction of the Appellate Court is certainly binding on the Court subordinate thereto. That apart in view of the provisions of Article 141 of the Constitution, all Courts in India are bound to follow the decisions of this Court. Judicial discipline requires and decorum known to law warrants that

appealate directions should be taken a binding and followed."

In ASSISTANT COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE Vs. DUNLOP INDIA LTD. (1985 I SCC p 260) at page 268 & 269, our Apex Court held;

"It is needless to add that in India under Article 141 of the Constitution the law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts within the territory of India and under Article 144 all authorities, civil and judicial in the territory of India shall Act in aid of the Supreme Court."

In SPENCER CO. LTD. Vs. VISWADARSHAN DIS-TRIBUTORS PVT. LTD. (1995 I SCC 259) our Apex Court held;

"The afore-narrated words, we think, are enough to assert the singular constitutional role of this Court, and correspondingly of the assisting role of all authorities, civil or judicial in the territory of India, towards it, who are mandated by the Constitution to Act in aid of this Court."

From these three decisions of our Apex Court it is clear that this tribunal has to follow the decision of the Supreme Court. Therefore, on the reasons stated by the various petitioners herein the decision of the Supreme Court binds this Tribunal.

14. Article 141 of the Constitution of India says;

"The law declared by the Supreme Court shall be binding on all Courts within the territory of India."

So, Article 141 of the Constitution of India further strengthens the contentions of the respondent departments that the above ruling of the Supreme Court is binding on this Tribunal.

15. An amendment to bring new provision for clause (1) and Section 9C and Sec. 33 was introduced by the Act 46 of 1982 and notification bringing into force of the said amendment is still awaited. In DES RAJ Vs. STATE OF PUNJAB (1988 II LLJ P 149) at page 162 our Apex Court held;

"We have not been able together as to why even six years after the amendment has been brought the definition of the Industry in section (J) of the Act the same has been brought to force. This Court on more than one occasion has indicated that the position should be clarified by an appropriate amendment and when keeping in view the opinion of this Court, the law was sought to be amended, it is appropriate that the same should be brought into force, as such or with such further alterations as may be considered necessary, and the legislative view of the matter is made known and the confusion in the field is cleared up."

"We make it clear that in the event of the definition of 'industry' being changed either by enforcement

of the new definition of industry or by an other legislative change, it would always be open to the aggrieved Irrigation department to raise the issue again and the present decision should not stand in the way of such attempt in view of the altered situation."

However, the amendment of Sec. 2 (j) has not come into force.

16. The petitioners have submitted a ruling in CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS Vs. JAGANNATH MARUTHIKONDHARE (1996 I LLJ P 1223) wherein on 6-12-95 our Supreme Court held that the forest department is an industry. We are not dealing with Forest Department in the instant case. In the said case a scheme known as Pachgaon Parwati Scheme "primarily intended to fulfil bio-aesthetic, recreational and educational aspirations of the people which will have inestimable in direct benefit of producing enlightened generation of conservationists of nature inclusive of forests and wild life for the future."

The Supreme Court held that the work undertaken by the forest department cannot be regarded as a part of the sovereign function of the State and so it was open to the respondent to invoke the provisions of the said Act. The present decision in Sub-Divisional Inspector of Post, Vaikkam Vs. Theyyam Joseph (1996 II LLJ P 230) was rendered by the Supreme Court, on 2-2-93, but in respect of different department. Since the above decision is not in respect of the Post, Telegraph and Telecommunication departments, the same cannot be taken into consideration.

17. The decision of the Central Administrative Tribunal in Padmavalli's case in full bench judgement of the Tribunal Vol. II, page 334 cannot go against the decision of the Supreme Court. The present decision of our Apex Court is binding on the Administrative Tribunal also. Though the International Labour Organisation in recommendation no. 119 para 4 has given the said right to the worker, the same has not been taken away by the present decision. If not before the Industrial Tribunal or the Labour Court the worker can have his say before some other forum. The other reason that Postal, Telegraph and Telephone workers cannot have the benefit of Sec. 11A of the Act, is also not a point relevant for our consideration. The Industrial workers alone are eligible to have the benefit of Sec. 11A. When once the employees of the Posts, Telegraphs and Telephone departments are taken as not "workman" within the meaning of I.D. Act, they cannot have such benefits. The further argument of the petitioners that if Postal, Telegraph and Telephone departments are to be excluded from the purview of the Industrial disputes Act, 1947 then no institution run by the Government can be held to an industry is a far reaching one and we need not offer any opinion.

18. From the foregoing discussion, it is clear that ruling of the Supreme Court in SUB DIVISIONAL INSPECTOR OF POSTS, VAIKKAM Vs. THEYYAM JOSEPH

(1996 II LLJ P 230) is binding on this Tribunal. Therefore, this Tribunal has no jurisdiction to decide the above industrial disputes pertaining to Posts, Telegraph and Telecommunications departments.

19. As this Tribunal has no jurisdiction to decide the various disputes raised against the Posts, Telegraph and Telecommunications department, since the disputes have been referred to this Tribunal for adjudication, the same cannot be returned and so all these disputes have to be dismissed by this Tribunal for want of jurisdiction.

In the result, award is passed dismissing the I.D. Nos. 53/92, I.D. 59/92, I.D. 12/93, I.D. 13/93, I.D. 17/93, I.D. 6/94, I.D. 145/94, I.D. 146/94, I.D. 162/94, I.D. 199/94, I.D. 200/94, I.D. 212/94, I.D. 213/94, I.D. 214/94, I.D. 215/94, I.D. 216/94, I.D. 1/95, I.D. 8/95, I.D. 9/95, I.D. 15/95, I.D. 29/95, I.D. 28/95, I.D. 45/95, I.D. 48/95, I.D. 49/95, I.D. 60/95, I.D. 62/95, I.D. 66/95, I.D. 71/95, I.D. 1/96, I.D. 161/94, I.D. 163/94, I.D. 70/95, I.D. 6/96, I.D. 9/96, I.D. 22/96, I.D. 34/96, I.D. 49/96, I.D. 50/96, I.D. 59/96, I.D. 73/96, I.D. 74/96, I.D. 75/96, I.D. 76/96, I.D. 77/96, I.D. 78/96, I.D. 79/96, I.D. 80/96, I.D. 81/96, I.D. 82/96 and I.D. 83/96 as not maintainable before this Tribunal. No costs.

Dated, this the 30th day of December, 1996.

S. THANGARAJ, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None

DOCUMENTS MARKED

For both sides : Nil

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 1997

का. आ. 1333:—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री भागेश्वर नायक धोरी को अगले आदेशों तक मुख्य खान निरीक्षक के अधीन खान निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं. ए-12025/10/95-आई.एस.एच.-11]

पाण्डेय अजय भूषण, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd May, 1997

S.O. 1333:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints Shri Bhageshwar Naik Dhori as Inspector of Mines Sub-ordinate to the Chief Inspector of Mines, until further orders.

[File No. A-12025/10/95-ISH. II]

PANDEY AJAY BIJUSHAN, Dy. Secy.